



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042023-245193
CG-DL-E-17042023-245193

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]
No. 96]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2023/चैत्र 23, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2023/CHAITRA 23, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अंतिम जांच परिणाम
नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023
(मामला सं. एडी (एसएसआर)-05/2022)

विषय: चीन जन. गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फोर्जर्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स" को छोड़कर "फोर्जर्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 07/13/2022-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड और वेलकास्ट स्टील्स लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) से चीन जन. गण. और थाईलैंड (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फोर्जर्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल को छोड़कर ग्राइंडिंग 2428 GI/2023

मीडिया बॉल्स (जिसे यहां बाद में "जीएम बॉल्स" अथवा 'संबद्ध सामान' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने की मांग करते हुए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 23 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या 14/34/2010-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फोर्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स" को छोड़कर ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स" के आयातों के संबंध में मूल जांच शुरू की थी। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/34/2010-डीजीएडी के माध्यम से जारी की गई थी, जिसमें संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 36/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये गये थे।
2. इसके बाद प्राधिकारी ने दिनांक 04 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 7/7/2017-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना दिनांक 11 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/7/2017-डीजीएडी के माध्यम से जारी की गई थी, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लागू शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 36/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाये गये थे। उक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाए गए थे और दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाले हैं।
3. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाये गये हों, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होने बंद हो जाएंगे और प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह समीक्षा करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

4. उपर्युक्तानुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करनी होती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र के मद्देनजर, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 7/13/2022-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
6. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पिछली जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

7. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार वर्तमान जांच शुरू करने से पूर्व निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2022 की जांच की शुरूआत की प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्धों देश के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों तथा आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।

घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

ङ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:

- (i) मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड ("मैगोटो थाईलैंड")।
- (ii) मैगोटॉक्स एलॉयड मैटेरियल (सूजौ) कंपनी लिमिटेड, चीन ("मैगोटॉक्स चीन")

च. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उपर्युक्त अधिसूचना का उत्तर दिया है और अनुरोध/निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- (i) मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अधिसूचना और प्रश्नावलियों की प्रति भेजी।

- (i) एसीसी लिमिटेड
- (ii) एलकॉन सीमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड
- (iii) अंबुजा सीमेंट लिमिटेड
- (iv) आंध्रा सीमेंट कंपनी लिमिटेड
- (v) अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड
- (vi) एशियन कंक्रीट एंड सीमेंट्स प्रा. लिमिटेड
- (vii) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
- (viii) बिनानी सीमेंट लिमिटेड
- (ix) बिडला कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- (x) सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
- (xi) सेंचुरी सीमेंट, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xii) रथ स्टील एंड पावर (पी) लिमिटेड

- (xiii) चौगुले एंड कंपनी लिमिटेड
- (xiv) चुनार चुर्क सीमेंट लिमिटेड
- (xv) डेक्कन सीमेंट्स लिमिटेड
- (xvi) डायमंड सीमेंट्स लिमिटेड
- (xvii) दुर्गा सीमेंट, आंध्रा सीमेंट्स लिमिटेड
- (xviii) ईसीओ सीमेंट इंडिया लिमिटेड
- (xix) ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xx) ग्रीन वैली इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
- (xxi) गुजरात सीधी सीमेंट लिमिटेड
- (xxii) गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
- (xxiii) हीडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड
- (xxiv) हिन्दुस्तान जिंक. लिमिटेड
- (xxv) इंडिया रिसोर्स लिमिटेड
- (xxvi) जेके सीमेंट लिमिटेड
- (xxvii) जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
- (xxviii) जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड
- (xxix) जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
- (xxx) जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
- (xxxi) काकतीय सीमेंट शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xxxii) कीर्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xxxiii) केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xxxiv) खैबर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड
- (xxxv) लाफार्ज इंडिया प्रा. लिमिटेड
- (xxxvi) मद्रास सीमेंट्स लिमिटेड
- (xxxvii) महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
- (xxxviii) माही सीमेंट (बांसवाडा) लिमिटेड
- (xxxix) बिडला कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- (xli) मंडोवी पेलेट्स लिमिटेड
- (xlii) मेघा टेक्निकल एंड इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड
- (xliii) मेघालय सीमेंट्स लिमिटेड
- (xlii) एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड
- (xliiv) मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xliv) माय होम सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xlv) एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xlvii) एनजीएस ब्हाइट सीमेंट कंपनी लिमिटेड
- (xlviii) ओसीएल इंडिया लिमिटेड
- (xlix) ओरेंट सीमेंट लिमिटेड
- (l) पानीपत थर्मल पावर स्टेशन
- (li) पण्यम सीमेंट्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (lii) परशक्ति सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (liii) पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (liv) प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड

(iv) रेन कमोडिटीज लिमिटेड
 (vi) रेसी सीमेंट लिमिटेड
 (vii) रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
 (viii) सागर सीमेंट्स लिमिटेड
 (ix) सलोनी इंडस्ट्रीज
 (x) समृद्धि सीमेंट लिमिटेड
 (xi) शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड
 (xii) सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड
 (xiii) शिवा सीमेंट लिमिटेड
 (xiv) श्री सीमेंट लिमिटेड
 (xv) श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी
 (xvi) डीसीएम श्रीराम लिमिटेड
 (xvii) सुडे मिनरल्स एंड केमिकल्स (पी) लिमिटेड
 (xviii) टाटा केमिकल्स लिमिटेड
 (xix) इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड
 (xx) त्रिनयनी सीमेंट (पी) लिमिटेड
 (xxi) ट्रैबू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 (xxii) यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
 (xxiii) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड
 (xxiv) वासवदत्त सीमेंट
 (xxv) जुआरी सीमेंट लिमिटेड

ज. उपर्युक्त पत्र के उत्तर में, किसी भी आयातक अथवा प्रयोक्ता ने आयातक/ प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिए/कानूनी अनुरोध दायर नहीं किए और/ अथवा हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत नहीं हुए।

झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात प्रयोक्ता एसोसिएशन को प्रश्नावलियां भेजीं।

(i) सीमेंट और निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय परिषद
 (ii) सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
 (iii) द इंडियन माइनिंग एंड इंजीनियरिंग जर्नल

ज. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, किसी भी प्रयोक्ता एसोसिएशन ने उत्तर नहीं दिया अथवा अनुरोध दायर नहीं किये और/अथवा हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत नहीं किया।

ट. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर, दिनांक 10 नवंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए समय बढ़ाया। प्राधिकारी ने दिनांक 03 फरवरी, 2023 के पत्र द्वारा अतिरिक्त सूचना दायर करने के लिए उत्तरदाता निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध पर और अधिक समय बढ़ाया। प्राधिकारी ने जांच प्रक्रिया के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मांगी।

ठ. चूंकि चल रही कोविड-19 महामारी के कारण वास्तविक सार्वजनिक फ़ाइल को बनाए रखना संभव नहीं था, अतः सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा दायर किए गए अनुरोधों/उत्तरों/टिप्पणियों के अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करें।

ड. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) है। अतः जांच अवधि 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि मानी गई है।

३. क्षति अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए डीजी सिस्टम से लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने तथा निर्यातकों द्वारा दायर किए गए उत्तरों के साथ तुलना और मिलान करने के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

४. आवेदकों और उत्तरदाता निर्यातकों/आयातकों से आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक और सूचना मांगी गई थी।

५. क्षतिरहित कीमत (जिसे यहां आगे "एनआईपी" कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर निर्धारित गई है। यह क्षतिरहित कीमत इस प्रकार निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

६. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 16 फरवरी, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध यदि कोई हैं, करें। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अगोपनीय अनुरोध साझा किए और उन्हें अपने खंडन की प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

७. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए तर्कों और दी गई सूचना पर उनकी साक्ष्य के साथ समर्थित होने की सीमा तक और वर्तमान जांच में संगत मानी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में विचार किया गया है।

८. प्राधिकारी ने इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया, जो संभावित सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना का आधार है और संगत तथा संभावित मानी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।

९. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का वास्तविक सत्यापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के प्रयोजन के लिए केवल ऐसी सत्यापित सूचना, जहां लागू हो, पर विश्वास किया गया है।

१०. कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रकोप और भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा वास्तविक आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के स्थल सत्यापन के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा वास्तविक निरीक्षण नहीं किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना का डेस्क सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने अपने अनुरोधों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

११. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

ब. इस जांच में अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बना है, हितबद्ध पक्षकारों को 05 अप्रैल, 2023 को जारी किया गया था, और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी देने के लिए 10 अप्रैल, 2023 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में, हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर जहां तक संगत पाया गया है, विचार किया गया है।

भ. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में रिकॉर्ड किया है।

म. इस अंतिम जांच परिणाम में **** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई दर्शाते हैं।

य. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 75.37 रुपये है।

ग. विचाराधीन और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. पिछली जांचों में प्राधिकारी द्वारा कोई पीसीएन पद्धति अधिसूचित नहीं की गई थी और उसे वर्तमान मामले में जारी रखा जाएगा।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद वही है जो पिछली जांचों में परिभाषित किया गया था। संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की समान वस्तु है जैसा कि पिछली जांचों में सिद्ध किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग ने पीसीएन पद्धति की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि घरेलू उद्योग और मैगोटॉक्स द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद की कीमतों में भारी अंतर है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"8. विचाराधीन उत्पाद 'ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स' (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर) है। 'ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स' (संक्षेप में, 'जीएम बॉल्स') विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए विभिन्न आकारों, स्वरूपों और रचनाओं में उत्पादित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह ग्राहकों की अलग-अलग आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग कठोरता में उपलब्ध है।

9. विचाराधीन उत्पाद का पाउडर बनाने के लिए सीमेंट निर्माण सामग्री, धातु खनन, कोयला धोल, थर्मल पावर प्लाट, केमिकल इंजीनियरिंग, सिरेमिक उद्योग, डोप उद्योग, हल्के उद्योग जैसे पेपरमेकिंग और चुंकीय सामग्री आदि में बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाता है। संबद्ध सामान सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय

73 के सीमा शुल्क उप-शीर्ष 7325 9100 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

11. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की समीक्षा का अनुरोध करने वाले किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान उत्पाद विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशों, तकनीकी विशिष्टताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित सामानों से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की 'समान वस्तु' हैं।

13. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति की आवश्यकता के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट किया है। तथापि, रिकार्ड में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि संबद्ध देशों से कोई आयात नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर भारत को कोई निर्यात नहीं दर्शाता है। यह भी नोट किया जाता है कि मूल जांच और पहली निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा किसी भी पीसीएन पद्धति को अधिसूचित नहीं किया गया था। इसलिए, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए पीसीएन परिभाषित नहीं किया है। तथापि, उचित तुलना के लिए जहां आवश्यक हो ग्रेड दर ग्रेड तुलना की गई है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यह समीक्षा याचिका त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वेलकास्ट स्टील्स लिमिटेड के लिए प्रारूप एक्स में कोई प्राधिकार पत्र/अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। वेलकास्ट स्टील्स लिमिटेड के लिए समर्थन का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

ख. अन्य घरेलू विनिर्माताओं ने याचिका में भाग नहीं लिया/समर्थन नहीं किया है। घरेलू उद्योग का लक्ष्य एकाधिकार करना और उन पर अपना परिचालन बंद करने के लिए दबाव डालना है।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

15. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड और वेलकास्ट स्टील्स लिमिटेड समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

ख. घरेलू उद्योग के अलावा, 11 अन्य घरेलू उत्पादक हैं जो मुख्य रूप से घरेलू मांग को पूरा करते हैं। चार घरेलू उत्पादकों से प्राप्त समर्थन पत्रों को प्राधिकारी के समक्ष कानूनी अनुरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ग. अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा गैर-भागीदारी इस तथ्य के कारण है कि वे (i) एमएसएमई हैं (ii) केवल घरेलू मांग को ही पूरा करते हैं (iii) उनके कोई निर्यात नहीं हैं।

घ. इस तर्क के संबंध में कि समीक्षा याचिका त्रुटिपूर्ण है, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदकों ने याचिका की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी विधिवत जांच की गई थी।

ड. जहां तक इस बात का संबंध है कि किसी अन्य घरेलू विनिर्माता ने भाग नहीं लिया है, घरेलू उद्योग ने शुल्कों को जारी रखने की मांग करते हुए अन्य घरेलू विनिर्माताओं के समर्थन पत्र प्रस्तुत किए हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाइट वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

17. यह आवेदन पत्र एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड और वेलकास्ट स्टील्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के 11 अन्य उत्पादक हैं। जांच की अवधि के दौरान, चार उत्पादकों ने आवेदन पत्र के समर्थन में समर्थन पत्र दायर किये हैं और पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध किया है।

18. प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर नोट करते हैं कि आवेदकों का भारतीय उत्पादन में ***% हिस्सा है और कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है; और नियम 2(ख) के अभिप्राय से संबंधित संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में उत्पाद के किसी आयातक अथवा प्रयोक्ता से संबद्ध नहीं हैं।

19. इसलिए, रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के संबंध में, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' हैं। यहां तक कि यद्यपि आधार की अपेक्षाएं समीक्षा जांच पर लागू नहीं होती हैं, तथापि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य, [2006 (202) ईएलटी 23 (एससी)] पर विश्वास किया गया है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

21. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. उत्तरदाता ने न केवल व्यापार सूचना, नियमावली और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, बल्कि इसके लिए उनकी व्याख्या भी बेतुकी और अतार्किक है। एच.आर. जॉनसन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2005(185) ईएलटी 125 (डीएल)] और डीजीटीआर के अन्य जांच परिणामों के मामले में सेसटेट के आदेश पर विश्वास किया गया है, जिसमें प्रतिक्रियाओं को गोपनीय दावा की गई सूचना के अर्थपूर्ण अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करने में विफलता के कारण खारिज कर दिया गया था।

ख. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिका अत्यधिक गोपनीय है, यह अनुरोध किया जाता है कि इस तर्क में काफी देर हुई है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, व्यापार सूचना के

अनुपालन न करने पर प्राधिकारी द्वारा मैगेटेओक्स को पहले ही बुलाया जा चुका है, जबकि आवेदकों को नहीं बुलाया गया है।

उ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना”

(1) नियम 6 के उप-नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

23. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की है। प्राधिकारी ने मैगोटॉक्स को व्यापार सूचना 10/2018 का पालन करने के बाद संशोधित उत्तर दायर करने का निर्देश दिया था। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो प्रकृति से गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटन एक प्रतियोगी के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा अथवा क्योंकि इसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर अथवा उस व्यक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे उस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की), अथवा जो एक जांच के लिए पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी जाती है, उचित कारण दर्शाएं जाने पर, प्राधिकारी द्वारा इस तरह माना जाएगा। ऐसी सूचना, प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जा सकती।

24. प्राधिकारी ने आवेदकों और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्तरदाता द्वारा शुरू में प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर पूरी तरह से अपर्याप्त और अत्यधिक गोपनीय था। तत्पश्चात, प्रतिवादियों को पूरी ईक्यूआर प्रस्तुत करने और गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी ने नोट किया है कि पुनः दायर किया गया उत्तर अत्यधिक गोपनीय बना हुआ है। नियम 7(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने उस सूचना की अवहेलना की है जो अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण के साथ नहीं है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर को उपलब्ध कराया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक पटल में उपलब्ध किसी भी सूचना को गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

च. विविध अनुरोध

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध

25. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. लंबे समय तक शुल्क लगाया जाना आसियान भागीदारों के बीच सहयोग की भावना के विरुद्ध है।
- ख. यदि शुल्क जारी रखा जाता है, तो घरेलू उद्योग को 10 वर्षों की निर्बाध अवधि के लिए शुल्क संरक्षण प्राप्त होगा।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

26. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. विभिन्न देशों में मैगोटॉक्स की विनिर्माण सुविधाओं ने व्यापार बाधाएं उत्पन्न की हैं, विभिन्न व्यापार कार्रवाईयों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा समाप्त की है, और केवल अपने उत्पादों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त व्यापार पहुंच को बनाए रखा है।
- ख. कानूनी आवश्यकता और निर्देश के बावजूद, मैगोटॉक्स थार्डलैंड की एक कंपनी से संबद्ध मैगोटॉक्स इंडिया वर्तमान जांच में भाग लेने में विफल रही है। यह मैगोटॉक्स के लिए एक आयातक, बिक्री और विपणन कार्यालय होने और क्षति की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री करने के बावजूद है।
- ग. उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर पूरी तरह से अपर्याप्त है और इसमें पर्याप्त प्रतिक्रिया का अभाव है। प्राधिकारी द्वारा मांगी गई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सार्थक सारांश प्रदान करने में विफलता से अपने हितों की रक्षा करने के लिए घरेलू उद्योग का अधिकार कर हुआ है।
- घ. क्षति अवधि के दौरान उत्पाद का कोई ज्ञात आयात नहीं हुआ है। एचएस कोड के तहत केवल नगण्य मात्रा दर्ज की गई है, जिनमें से कीमत मात्रा के अनुपात में अत्यधिक है। घरेलू उद्योग प्राधिकारी से रिपोर्ट की गई मात्रा की जांच करने का अनुरोध करते हैं।
- ঙ. आयातों की मात्रा कम होने की स्थिति में भी, पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जा सकता है। भारत, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित विभिन्न न्यायालयों के मामलों पर विश्वास किया गया है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

27. प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है और निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि यदि यह पाया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति होने की संभावना है तो समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाया जाना आवश्यक है। पाटनरोधी कानून अनुचित व्यापार परिपाटी को हटाने और घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए है। प्राधिकारी कानूनों के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करने के बाद ही पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।
- ख. यह नोट किया जाता है कि मैगोटॉक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड ने सुनवाई में भाग लिया। तथापि, कई निर्देशों और आवश्यकता के बावजूद, कंपनी ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और वर्तमान जांच में संगत सूचना नहीं दी गई है। व्यापार सूचना 11/2018 के उल्लंघन में, मैगोटॉक्स इंडिया ने खुद को वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया है। इसके बावजूद मैगोटॉक्स इंडिया के प्रतिनिधि ने

मौखिक सुनवाई में भाग लिया और मैगोटॉक्स थाईलैंड के समर्थन में बात की। भले ही प्राधिकारी ने मैगोटॉक्स इंडिया के संबंध में संगत सूचना देने के लिए मैगोटॉक्स थाईलैंड को निर्देशित किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैगोटॉक्स इंडिया द्वारा वांछित सूचना नहीं दी गई थी। प्राधिकारी मानते हैं कि मैगोटॉक्स इंडिया से उत्तर वर्तमान जांच में संगत और आवश्यक था, क्योंकि मैगोटॉक्स थाईलैंड ने उल्लेख किया कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में वह भारत को उत्पाद का निर्यात करना चाहता है, मैगोटॉक्स इंडिया वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू बाजार में माल बेच रहा है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैगोटॉक्स थाईलैंड के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से देखा जाता है, मैगोटॉक्स इंडिया वर्तमान में उत्पादन में लगी हुई है, जबकि यह केवल एक विपणन शाखा थी जैसा कि मूल जांच में पाया गया था।

ग. मैगोटॉक्स थाईलैंड द्वारा दायर सूचना की पर्याप्तता के संबंध में, प्राधिकारी ने मैगोटॉक्स थाईलैंड को त्रुटिपूर्ण प्रश्नावली जारी की जिससे उन्हें उत्तर पूरे करने का अवसर प्राप्त हुआ। तथापि, कई अवसर देने के बावजूद, मैगोटॉक्स थाईलैंड ने प्राधिकारी द्वारा वांछित निम्नलिखित सूचना नहीं दी है:

- (i) 2021-22, 2019-20 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।
- (ii) पिछले तीन वर्षों के लिए लाभप्रदता विवरण।
- (iii) निष्पादन मानदंड जो प्रवृत्ति में हैं।
- (iv) लागत और बिक्री आंकड़ों में भिन्नता।

घ. मैगोटॉक्स थाईलैंड ने अपनी धमता, उत्पादन लागत और बिक्री के संबंध में अपनी प्रश्नावली के उत्तरों में दी गई सूचना के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये हैं। तथापि, 5 अप्रैल, 2023 को लगभग पूर्वाहन 01:40 बजे मैगोटॉक्स थाईलैंड के कानूनी सलाहकार से एक ई-मेल प्राप्त हुआ। जब प्राधिकारी प्रकटन विवरण जारी करने की प्रक्रिया में थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक को वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी को संगत सूचना देने के लिए कई अवसर दिए गए थे। तथापि, निर्यातक ने समय सीमा के दौरान संगत सूचना नहीं दी है। प्राधिकारी द्वारा प्रकटन जारी करने के चरण में निर्यातक द्वारा दायर किए गए दस्तावेज काफी विलंबित और समयबाधित हैं। इसलिए प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के उद्देश्य से इतने विलंबित चरण में उक्त निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों को स्वीकार नहीं करते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने उन्हें उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर तथ्यों सिद्ध किये हैं।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध

28. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

29. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि चीन में लागत और कीमतें उचित रूप से बाजार बलों को नहीं दर्शाती हैं। अतः, प्राधिकारी अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।

ख. पैरा 7 के तहत, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध सामानों की कीमतों के आधार पर अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत

अथवा किसी अन्य उपयुक्त आधार पर कीमत के आधार पर निर्धारित की जानी होती है। आवेदकों ने वर्तमान जांच के लिए थार्डलैंड को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में बताया है।

ग. थार्डलैंड के लिए सामान्य मूल्य की गणना देश में संबद्ध सामान के एकमात्र उत्पादक मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थार्डलैंड द्वारा बेचे गए सामानों की लागत और उचित लाभ मार्जिन के आधार पर की जानी चाहिए।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

30. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो;
- (ख) अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्धम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्धम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

चीन में सामान्य मूल्य

31. चीनी अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद- VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद- VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैं:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सम्भव अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसम्भायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसम्भायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाठनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन समिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

32. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में इस प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

33. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

34. नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 7 निम्नानुसार है:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।

35. चीन में किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने जांच में सहयोग नहीं किया है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और किसी भी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान के खंडन के अभाव में, प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उपर्युक्त मानते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं।

चीन जन. गण. के सभी उत्पादक/निर्यातक

36. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निहित अन्य तरीकों के संबंध में रिकॉर्ड में पर्याम सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने "कोई अन्य उचित आधार" पद्धति अपनाकर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

37. इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है।

शाईलैंड के निर्यातक/उत्पादक मैसर्स मैगेटॉक्स कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

38. उत्तरदाता के प्रश्नावली के उत्तर की जांच करते समय, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में आंकड़ों में काफी भिन्नताएं हैं। यह देखा जाता है कि;

क. यद्यपि जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के लिए तीसरे देशों के लेनदेन-वार बिक्री आंकड़ों के संबंध में किए गए अनुरोधों में परिशिष्ट 1 में तीसरे देशों को निर्यात की मात्रा *** मी. टन दर्शाई गई है, तथापि उत्तरदाता ने *** मी. टन का निर्यात सूचित किया। यह स्पष्ट नहीं है कि इस लेन-देन वार बिक्री में एनपीयूसी बिक्री शामिल है अथवा नहीं।

ख. कंपनी का वित्तीय विवरण, पिछले 3 वर्षों से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होने के बावजूद, उत्तरदाता ने केवल एक प्रस्तुत किया है। अनुबंध 8 में, जिसमें 2020-2021 के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिसमें जांच की 9 माह की अवधि शामिल है, यह देखा जाता है कि कंपनी को 2021 में *** मिलियन भाट की हानि और 2020 में *** मिलियन भाट की हानि हुई, जबकि परिशिष्ट 7 में, कंपनी ने समग्र रूप से कंपनी के लिए *** मिलियन भाट का लाभ, विचाराधीन उत्पाद में *** मिलियन भाट का लाभ और एनपीयूसी में *** मिलियन

का लाभ सूचित किया। यह दर्शनि के लिए उत्तर में कोई पुनर्समाधान नहीं दिया गया है कि 2021 में *** मिलियन की हानि जांच की अवधि में *** मिलियन भाट के लाभ में कैसे बदल गई।

ग. तीसरे देश में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के भाग-II के अनुबंध 1 में रिपोर्ट किए गए लेन-देन-वार आंकड़ों, रिपोर्ट किए गए अंतर्देशीय मालभाड़े में प्रति यूनिट असामान्य लागत दिखाई देती है, जो कि *** भाट प्रति मी. टन से लेकर *** भाट प्रति मी. टन तक अधिक है। अंतर काफी हैं क्योंकि इसे कारखाने से बंदरगाह तक माल परिवहन के लिए लगाया जाता है। इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया को निर्यात के संबंध में समुद्री भाड़ा 88 भाट प्रति मी. टन जितना कम से लेकर *** भाट प्रति मी. टन जितना अधिक होता है, और तुर्की *** भाट प्रति मी. टन जितना कम से लेकर *** भाट प्रति मी. टन जितना अधिक होता है। यह भारी अंतर एक ही देश के लिए उसी तारीख के दौरान लेनदेन पर भी देखा जाता है जैसे कि तुर्की - 30 अगस्त - भाड़ा *** भाट प्रति मी. टन और *** भाट प्रति मी. टन और, ऑस्ट्रेलिया के लिए - 8 अप्रैल - रिपोर्ट किया गया समुद्री भाड़ा *** भाट प्रति मी. टन से *** भाट प्रति मी. टन तक भिन्न होता है।

39. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा अपनी अनुरोधों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश और इसके लिए 10 दिनों की समय-सीमा प्रदान करने के बावजूद, उत्तरदाताओं ने डेस्क-सत्यापन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

थाईलैंड के अन्य सभी निर्यातकों/उत्पादकों का सामान्य मूल्य

40. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, निर्यातक/उत्पादक थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक/निर्यातक है। थाईलैंड से सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है।

चीन जन. गण. और थाईलैंड की निर्यात कीमत का निर्धारण

41. चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत का व्यौरा देते हुए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। डीजी सिस्टम्स के आंकड़े चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात न होना दर्शाते हैं।

42. जहां तक थाईलैंड का संबंध है, मैसर्स मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड ने जांच में उत्तर दिया है और उल्लेख किया है कि उन्होंने भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के माध्यम से इसे सत्यापित किया है।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबंधित उत्पाद का कोई ज्ञात आयात नहीं हुआ है। इसलिए, जांच की अवधि के निर्यातों के संबंध में वास्तविक पाटन मार्जिन को जांच की अवधि के दौरान भारत में वास्तविक आयातों के अभाव में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

पाटन और क्षति के जांच के लिए पद्धति और मात्रात्मक प्रभाव

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध

44. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग काफी निर्यातोन्मुख है और शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में क्षति के बार-बार होने का आरोप नहीं लगा सकता है।

ख. प्राधिकारी को संरक्षण की असामान्य रूप से लंबी अवधि की आवश्यकता और घरेलू उद्योग की अंतर्निहित अक्षमताओं की जांच करनी चाहिए जो उनकी क्षति का कारण है। सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका से कास्टिक सोडा (1 अगस्त, 2018), जापान और थाईलैंड से फिनोल, (1 जुलाई, 2016), चीन जन. गण., इंडोनेशिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से सादा जिप्सम प्लास्टर बोर्ड (19 अप्रैल, 2018) से आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा पर विश्वास किया जाता है।

ग. शुल्क लागू होने के दौरान घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में आई गिरावट मैगेटॉक्स की गलती नहीं है।

घ. क्षतिरहित कीमत के परिकलन में कोविड-19 और क्षमता विस्तार को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप व्याज की लागत और मूल्यहास में वृद्धि हुई है।

ड. अवास्तविक प्रस्तावों के आधार पर क्षति के परिकलन में कोई औचित्य नहीं है जो ग्रेड अथवा पीसीएन का कोई व्यौरा न होने वाले घरेलू उद्योग से अलग-अलग और भिन्न हैं।

च. कोई मात्रात्मक क्षति, कीमत क्षति, अथवा लाभप्रदता, बिक्री लागत, संस्थापित क्षमता आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

छ. शुल्कों के संरक्षित वातावरण के तहत काम कर रहे वेलकास्ट को अभी भी हानि हो रही है।

ज. यह दावा करने में कोई औचित्य नहीं है कि अन्य क्षेत्राधिकारों में घरेलू उद्योग पर लगाए गए शुल्कों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने इनमें से किसी भी शुल्क को चुनौती तक नहीं दी है। उनका दावा निराधार है।

झ. अन्य क्षेत्राधिकारों में घरेलू उद्योग पर लगाए गए शुल्क दर्शाते हैं कि वे विचाराधीन उत्पाद के लिए अधिक कीमत वसूल कर भारतीय घरेलू प्रयोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

45. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने निरंतर पाटन अथवा क्षति का दावा नहीं किया है। वास्तव में शुल्क की मौजूदगी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों में उपयुक्त सुधार हुआ है।

ख. यद्यपि संबद्ध देशों से कोई अथवा नगण्य आयात नहीं है, फिर भी विदेशी निर्यातकों के पास पर्याप्त मुक्त रूप से निपटानयोग्य क्षमता मौजूद है। विभिन्न न्यायाधिकरणों में की गई जांचों का संदर्भ दिया जाता है।

ग. वर्तमान पाटन अथवा क्षति का अभाव यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि शुल्क जारी नहीं रखा जाना चाहिए।

घ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग निर्यातोन्मुख है, यह अनुरोध किया जाता है कि वे घरेलू उत्पादक हैं न कि निर्यातोन्मुख यूनिट। इसके अतिरिक्त, वैश्विक बाजार में संबद्ध सामानों के अग्रणी उत्पादकों में से एक के रूप में, घरेलू उद्योग निर्यात में लगा हुआ है।

ङ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग की उपलब्ध क्षमता और विस्तार में पाटन का कोई खतरा नहीं है, यह अनुरोध किया जाता है कि विस्तार का संबद्ध देशों से सामना किए जा रहे पाटन के खतरे से कोई संबंध नहीं है।

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | जांच की अवधि |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------------|
| घरेलू उद्योग की विक्रियां | मी. टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 81 | 103 | 114 |
| अन्य घरेलू उत्पादकों की विक्रियां | मी. टन | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 100 | 100 |
| समग्र रूप में संबद्ध देश | मी. टन | 246 | 135 | 63 | 0 |
| अन्य देश | मी. टन | 83 | 120 | 9 | 52 |
| मांग/खपत | मी. टन | 96,905 | 89,800 | 97,889 | 1,01,841 |

#अन्य घरेलू उत्पादकों की विक्री को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत बाजार सूचना से उनकी संस्थापित क्षमता के रूप में लिया गया है।

च. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि लंबे समय तक संरक्षण आसियान की भावना के विरुद्ध है और यह उद्योग की अक्षमता है जिसके कारण धनि हुई है, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदकों द्वारा किसी धनि का दावा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उस अवधि पर कोई रोक नहीं है जिसके लिए शुल्क बढ़ाया जा सकता है। भारत, यूरोपीय संघ, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न जांचों का संदर्भ दिया गया है जहां शुल्कों को 15-30 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

छ. जहां तक वित्तीय स्थिति में गिरावट के विवाद का संबंध मैगोटॉक्स से नहीं है, वहां कोई मात्रात्मक धनि, कीमत धनि अथवा निष्पादन मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, आवेदक अनुरोध करते हैं कि उन्होंने निरंतर धनि का दावा नहीं किया है अथवा यह कि मैगोटॉक्स ने उन्हें धनि पहुंचाई है।

ज. इस तर्क के संबंध में कि धनिरहित कीमत के परिकलन में कोविड-19 और अन्य प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, धनिरहित कीमत का परिकलन निर्धारित नियमावली और परिपाठियों द्वारा शासित होगी।

झ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि ग्रेड अथवा पीसीएन का कोई व्यौरा न होने वाले अवास्तविक प्रस्तावों के आधार पर धनि के परिकलन करने में कोई औचित्य नहीं है, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन करें जिनमें ग्रेडों का विवरण है।

ज. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि शुल्क द्वारा संरक्षित होने के बावजूद वेलकास्ट को हानि हो रही है, यह अनुरोध किया जाता है कि ये हानि पाटन के कारण नहीं हैं। घरेलू उद्योग वेलकास्ट में संबद्ध सामानों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया में है और इसके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में कमी आई है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

46. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच का प्रावधान (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव।
47. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया तो उसे लगाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद निष्प्रभावी हो जाता है, बर्तने कि यदि केन्द्र सरकार समीक्षा में, यह राय व्यक्त करे कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह समय समय पर आगे पांच वर्षों की अवधि या ऐसी आगामी अवधि जो समय बढ़ाने के आदेश की तारीख से शुरू होगी, के लिए उसके लागू होने की अवधि को बढ़ा सकती है।
48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्योंकि यह पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है इसलिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के जारी रहने तथा वास्तविक क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के वास्तविक या संभावित आयातों के संदर्भ में कर सकती है।
49. प्राधिकारी ने शुल्क के समाप्ति की स्थिति में, घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि वर्तमान जांच सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क) के अनुसार शुरू की गई है जिसमें प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क को आगे पांच वर्षों के लिए जारी रखने की आवश्यकता है और संभावित पाटन और क्षति की मात्रा तथा विस्तार कितना है और जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों के आधार पर क्या शुल्क को जारी रखने या हटाने की आवश्यकता है। क्षति अवधि के दौरान वर्तमान क्षति का आकलन करने या उसके जारी रहने की समीक्षा करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों की जांच की है।
50. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच पहले की है।
51. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट आए, कुछ मापदंडों में गिरावट दिख सकती है, जबकि कुछ में नहीं। प्राधिकारी क्षति संबंधी सभी मापदंडों पर विचार करते हैं और तत्पश्चात निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन की वजह से क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और तथ्यों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।
52. वर्तमान मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयात नहीं हैं। अतः, किसी भी तरह, घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है। फिर भी, प्राधिकारी ने वर्तमान क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच की है।
53. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क से संरक्षित होने के बावजूद वेलकास्ट को घाटा होना जारी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये घाटे पाटन के कारण नहीं हुए हैं। घरेलू उद्योग का तर्क है कि वह वेलकास्ट में संगत वस्तु का उत्पादन बंद करने की प्रक्रिया में है और इसलिए उसने क्षमता उपयोग कम कर दिया है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

(i) मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

54. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत पर घरेलू उद्योग और अन्य सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों, डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से आयातों और सभी अन्य देशों से आयात के योग के रूप में विचार किया है।

55. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है।

(ii) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

56. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। अति विशेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से आयात की मात्रा पर भरोसा किया है। वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है:

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | पीओआई |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|-------|
| समग्र रूप से संबद्ध देश | एमटी | 246 | 135 | 63 | 0 |
| अन्य देश | एमटी | 83 | 120 | 9 | 52 |
| निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात | | | | | |
| खपत | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 59 | 25 | 0 |
| भारतीय उत्पादन | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 57 | 28 | 0 |
| कुल आयात | % | 75 | 53 | 88 | 0 |

57. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से गिरावट आई है। इसके अलावा, वर्तमान पीओआई में संबद्ध देशों से उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

(i) कीमत कटौती

58. चूंकि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के कोई ज्ञात आयात नहीं हुए हैं, इसलिए यह निष्कर्ष है कि संबद्ध आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हुई है।

(ii) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

59. यह निर्धारित करने के लिए क्या घरेलू उद्योग कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव से ग्रस्त है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों की प्रवृत्ति पर विचार किया है। तथापि, चूंकि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई ज्ञात आयात नहीं हुआ है, इसलिए यह निष्कर्ष प्रस्तावित है कि संबद्ध आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ा है। नीचे तालिका में बाजार में घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों के रुक्कानों के संबंध में वास्तविक स्थिति दर्शाई गई है।

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | पीओआई |
|-------------|----------|---------|---------|---------|-------|
| बिक्री लागत | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 102 | 99 | 133 |
| बिक्री कीमत | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 88 | 113 |

60. यह देखा गया है कि उत्पादन लागत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि में पूरी तरह प्रदर्शित नहीं होती है। तथापि, घरेलू उद्योग ने बताया है कि विदेशी उत्पादकों द्वारा शुल्क समाप्ति की स्थिति में घरेलू बाजार में क्षतिकारी कीमत पर उत्पाद का पाटन करने की संभावना है, और यदि ऐसा होता है, तो बाजार में कीमत ह्रास होगा जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

61. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में किए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार करते हुए क्षति मापदंडों की जांच की है।

(i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

62. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग को नीचे तालिका में दिया गया है:

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | पीओआई |
|-------------------|------------|---------|---------|---------|-------|
| क्षमता | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 117 | 117 | 117 |
| उत्पादन | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 91 | 97 |
| क्षमता उपयोग | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| प्रवृत्ति | %/सूचीबद्ध | 100 | 81 | 77 | 83 |
| घरेलू बिक्रियां | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 81 | 103 | 114 |
| निर्यात बिक्रियां | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 97 | 91 | 94 |

63. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने 2019-20 में अपनी स्थापित क्षमता में वृद्धि की है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2020-21 तक गिरावट आई और पीओआई में वृद्धि हुई है। घरेलू बिक्री मात्राएं 2019-20 तक कम हुई हैं और उसके बाद पीओआई तक बढ़ी हैं।

(ii) मांग में बाजार हिस्सा

64. घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादक, संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | पीओआई |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|-------|
| सभी घोतों से आयात | % | 0.34% | 0.28% | 0.07% | 0.82% |
| घरेलू उद्योग की विक्री | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 88 | 102 | 108 |
| अन्य घरेलू उत्पादकों की विक्रियां | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 108 | 99 | 95 |

65. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का हिस्सा 2019-20 में कम हुआ है परंतु उसके बाद बढ़ा है। संबद्ध आयातों का हिस्सा पूरी क्षति अवधि में शून्य (1 प्रतिशत से कम) रहा है।

(iii) मालसूची

66. अति अवधि और पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | पीओआई |
|-------------|----------|---------|---------|---------|-------|
| औसत मालसूची | एमटी | 5,413 | 7,551 | 7,853 | 7,630 |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 140 | 145 | 141 |

67. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बढ़ी है और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इसमें गिरावट आई है।

(iv) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

68. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय नीचे तालिका में दी गई है:

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | पीओआई |
|----------------------|----------|---------|---------|---------|-------|
| लाभ/हानि(पीबीटी) | रु./एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 74 | 48 | 41 |
| कुल लाभ/हानि(पीबीटी) | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 60 | 50 | 46 |
| पीबीआईटी | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 60 | 50 | 46 |
| नकद लाभ | लाख रु. | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 63 | 56 | 56 |
| निवेश पर आय | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 62 | 60 | 40 |

69. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओआई में क्षति अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है।

(v) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

| विवरण | यूओएम | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | पीओआई |
|--------------------------|----------|---------|---------|---------|-------|
| कर्मचारियों की संख्या | संख्या | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 91 | 77 | 69 |
| प्रति कर्मचारी उत्पादकता | एमटी | *** | *** | *** | *** |
| प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 105 | 119 | 141 |

70. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों में क्षति अवधि में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि में और विशेष रूप से पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि ये मापदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव नहीं दर्शाते हैं।

(vi) वृद्धि

71. यद्यपि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि, मात्रा और कीमत मापदंडों के संबंध में ऋणात्मक रही थी, परंतु मात्रा मापदंडों में वृद्धि पीओआई में सकारात्मक हुई, कीमत मापदंडों में वृद्धि ऋणात्मक रही है।

(vii) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

72. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति होने का दावा किया है।

(viii) क्षति मार्जिन की मात्रा

73. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। पीयूसी की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/अंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। इस एनआईपी पर क्षति निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार सुविधाओं के साथ भी किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय उत्पादन लागत में नहीं जोड़े जाएं। नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियां, औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्क संगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की क्षति रहित कीमत ज्ञात करने हेतु कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और उसका पालन किया गया। इस प्रकार निर्धारित एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु विचार किया गया है।

74. चूंकि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कोई आयात नहीं हुए हैं, इसलिए जांच अवधि के दौरान निर्यातों पर आधारित क्षति मार्जिन की गणना नहीं की गई है। तथापि, प्राधिकारी ने संभावना जांच के लिए परिकलित एनआईपी पर भरोसा किया है।

क्ष. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

75. प्राधिकारी ने संबद्ध आयातों से इतर ऐसे किसी अन्य ज्ञात कारक की जांच की है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया

जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रभाएं और घरेलू तथा विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

76. यह देखा गया है कि अन्य देशों से मामूली आयात हुए हैं। इस प्रकार, तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती है।

ख) मांग में संकुचन

77. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है।

ग) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

78. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में किसी वास्तविक परिवर्तन (नों) के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से प्रतिस्पर्धा की दशाओं में किसी परिवर्तन या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का पता नहीं चला है।

ङ.) प्रौद्योगिकी में विकास

80. किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा मौजूदा प्रौद्योगिकी में किसी विकास/परिवर्तन का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार के अनुसार उसके निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, इसके लिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

82. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने उन्हें स्वीकार किया है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

83. किसी भी तरह, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदकों को संबद्ध आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने/उनके पुनरावृत्ति होने की संभावना

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध

84. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) में पाटन, उपलब्ध क्षमता, कीमत प्रभाव की दर और मालूसची जैसे कारकों का आकलन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। जिंदल सॉलिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2021 (376) ईएलटी 107 (टीआरआई-दिल्ली)], हुबर्ड ट्राई-रिंग फोरजिंग कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2016 (342) ईएलटी 473 (टीआरआई-दिल्ली)], और निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ [2017 (358) ईएलटी 146 (गुजरात)] का भी उल्लेख किया गया है।

ख. आयातों में काफी अधिक वृद्धि की संभावना की कोई मान्यता नहीं की गई है क्योंकि कोई संबद्ध आयात नहीं हैं।

ग. मागोटियाक्स के संयंत्र केवल भारत को समर्पित नहीं हैं और पाटनरोधी शुल्क लगाने के दस वर्ष के दौरान अनेक बाजारों के लिए विकसित किए गए हैं।

घ. घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता और उनके द्वारा किया गया अतिरिक्त विस्तार यह दर्शाता है कि पाटन का कोई खतरा नहीं है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा भागीदारी या प्रस्ताव के संबंध में कोई सूचना निर्यातकों के पास उपलब्ध नहीं है।

च. निर्यातक ने मूल जांच और एसएसआर के बाद से तीसरे देश के बाजार में भारी वृद्धि की है।

छ. मागोटियाक्स इंडिया से यह पता चला है कि कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पाद भारत में स्थानीय रूप से स्वतंत्र पक्षकारों द्वारा ठेके पर बनाए गए थे।

ज. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान मागोटियाक्स इंडिया के कंट्री मैनेजर की उपस्थिति के संबंध में व्यापार सूचना सं. 11/2018 का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने किसी भी पक्षकार, चाहे हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत हो अथवा नहीं, को सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने और प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां देने की स्पष्ट रूप से अनुमति दी है।

झ. मागोटेक्स इंडिया और मागोटेक्स थाइलैंड संबंधित सामूहित कंपनियां हैं परंतु एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करती हैं। मागोटेक्स थाइलैंड के पास मागोटेक्स इंडिया की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

ञ. मागोटेक्स इंडिया के लिए वर्तमान जांच में सहयोग करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि (i) वे पीयूसी के संबद्ध देश में निर्यातक नहीं हैं, (ii) उन्होंने पीओआई में पीयूसी का आयात नहीं किया है और (iii) वे वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में नामांकित नहीं हैं। एलिमा मैटिरियल्स टेक्नोलॉजी (जियांगसु) कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ [डब्ल्यू. पी. (सी) 12894/2022 में दिनांक 6 सितंबर, 2022 के आदेश] का उल्लेख किया गया है।

ट. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कीमत ऑफर त्रुटिपूर्ण और मनगढ़ंत हैं।

ठ. कंपनी के पास मानकीकृत उत्पादों की *** एमटी मालसूची (31 मार्च, 2022 के अनुसार) है और गैर-मानकीकृत उत्पाद आदेशों के तहत विनिर्मित और आपूर्ति किए गए हैं।

ड. चूंकि मूल जांच के बाजार जहां पर बिक्री में वृद्धि हुई है मध्य-पूर्व (2219%), यूरोप (1541%), आस्ट्रेलिया (452%) और दक्षिण अमेरिका (214%) हैं।

ढ. पूर्ववर्ती जांच से बिक्री में वृद्धि वाले बाजारों में दक्षिण अमेरिका (7349%) और आस्ट्रेलिया (259%) शामिल हैं।

ण. मागोटेक्स इंडिया से मांगी गई सूचना की प्रकृति की वर्तमान जांच में कोई प्रासंगिकता नहीं है और वे मागोटेक्स इंडिया के व्यापार गुप्त सूचना है।

ज.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

85. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- वर्तमान अवधि में आयातों में गिरावट पाठनरोधी शुल्क लागू होने के कारण आई है। यदि शुल्क समाप्त होता है तो भारी मात्रा में पाठन पुनः शुरू हो जाएगा।
- संबद्ध देशों के उत्पादकों का पाठन का इतिहास रहा है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है और उसके पास इस्पात और एलुमिना खनन में उत्पादन और परिवर्तन लागत में पर्याप्त बढ़त है जो भारत को संबद्ध वस्तु का एक लाभकारी बाजार बनाती है।
- विदेशी उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य और संभावित क्षमताएं हैं। विचाराधीन उत्पाद संबंधी हाल में समाप्त हुई एसएसआर में आस्ट्रेलियाई आयोग द्वारा चीन में अधिकृत क्षमता देखी गई है।
- संबद्ध देशों में उत्पादक काफी अधिक निर्यातोन्मुख हैं और दूसरे देशों को भारी पाठन कर रहे हैं।
- चूंकि संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है इसलिए मागोटेक्स इंडिया बाजार में घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों का उद्धम बताए बिना अपने उपभोक्ताओं को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।
- मेगोटेक्स इंडिया पार्टिट और क्षतिकारी कीमत पर उत्पाद की पेशकश करके भारतीय बाजार में ब्रांड स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
- जैसा कि प्रस्तावों से देखा जा सकता है, मागोटेक्स इंडिया रायपुर, छत्तीसगढ़ की भांडागार-द्वार कीमतों पर उपभोक्ताओं को उत्पाद की पेशकश कर रहा है। दिए गए ऑफर के अनुसार निर्धारित पाठन और क्षति मार्जिन निम्नानुसार काफी अधिक है:

क. पूर्ववर्ती पेशकश:

| विवरण | मात्रा | पाठन मार्जिन | | श्रेणी | क्षति मार्जिन | | श्रेणी |
|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | | (एमटी) | (डॉ./एमटी) | % | (डॉ./एमटी) | % | |
| पेशकश 1 | *** | *** | ***% | 100-110 | *** | ***% | 20-30 |
| पेशकश 2 | *** | *** | ***% | 60-70 | *** | ***% | 0-10 |
| पेशकश 3 | *** | *** | ***% | 180-190 | *** | ***% | 50-60 |
| पेशकश 4 | *** | *** | ***% | 80-90 | *** | ***% | 10-20 |
| कुल | *** | *** | ***% | 80-90 | *** | ***% | 10-20 |

ख. वर्तमान पेशकश:

| विवरण | मात्रा | पाठन मार्जिन | | श्रेणी | क्षति मार्जिन | | श्रेणी |
|---------|--------|--------------|------------|--------|---------------|------|--------|
| | | (एमटी) | (डॉ./एमटी) | % | (डॉ./एमटी) | % | |
| पेशकश 1 | *** | *** | ***% | 10-20 | *** | ***% | 10-20 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| पेशकश 2 | *** | *** | ***% | 20-30 | *** | ***% | 20-30 |
| पेशकश 3 | *** | *** | ***% | 10-20 | *** | ***% | 10-20 |
| पेशकश 4 | *** | *** | ***% | 10-20 | *** | ***% | 20-30 |
| कुल | *** | *** | ***% | 10-20 | *** | ***% | 20-30 |

ज. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा मागोटेक्स की कीमत के बराबर अपनी कीमत को कम करने की स्थिति में घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन की जांच करनी चाहिए। यह देखा जाए कि घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा और निवेशों पर ऋणात्मक आय से नुकसान झेलना पड़ेगा, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है:

| विवरण | यूआरएम | वास्तविक | पेशकश कीमत के अनुसार |
|---|----------|----------|----------------------|
| प्रति यूनिट निवल बिक्री वसूली | रु./एमटी | *** | *** |
| पीबीटी (कर पूर्व लाभ) | रु./एमटी | *** | (***) |
| पीबीआईटी (ब्याज और कर पूर्व लाभ) | रु./एमटी | *** | (***) |
| नकद लाभ (पीबीटी+ मूल्यहार) | रु./एमटी | *** | (***) |
| औसत नियोजित पूंजी (आरओआई) के प्रतिशत रूप में पीबीआईटी | % | ***% | (***)% |

झ. मागोटेक्स ने तीसरे देश को पाटन किया है जिससे भारी कीमत कटौती संभावित आदेशों का नुकसान और अनेक देशों को कीमत क्षति हुई है।

ज. जैसा कि इक्यूआर में बताया गया है भारत में पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क के आदेश के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी ने 72 बाजार विकसित किए हैं। इसके अलावा, शुल्क समाप्ति की स्थिति में कंपनी का इरादा केवल भारत को निर्यात करने का है।

ट. प्रतिवादी ने भारतीय बाजार में इरादतन बिक्री के बावजूद उत्पादन क्षमता में किसी बदलाव का दावा नहीं किया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके पास अप्रयुक्त क्षमताएं हैं, वे भारत को अन्य बाजारों के उत्पाद बेचना चाहते हैं और भारतीय बाजार काफी कीमत आकर्षक हैं।

ठ. आवेदकों के संभावित और आशंकित निष्पादन के आकलन से पता चलता है कि घरेलू उद्योग पाटन की अनुपस्थिति में काफी बेहतर कर सकता था और यदि शुल्क समाप्त होता है तो उसे नुकसान हो सकता है।

ड. प्रतिवादी के इस तर्क के संबंध में कि कोई संभावना निर्धारित नहीं हो सकती है क्योंकि आयातों की मात्रा शून्य तक कम रही है, यह बताया गया है कि पाटन और क्षति की भरपाई लागू शुल्क द्वारा की गई है। इसके अलावा, पीओआई के दौरान आयातों में कमी से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि शुल्क हटने पर बाजार में आयातों की भरमार हो जाएगी।

ढ. इस तर्क के संबंध में कि मागोटेक्स का संयंत्र केवल भारत को आपूर्ति के लिए समर्पित नहीं है, प्रतिवादी ने स्वयं बताया है कि जब शुल्क लागू हुआ तो उन्होंने क्षमताओं के उपयोग के लिए 72 से अधिक बाजार तैयार किए। लाजिस्टिक्स आर्थिक रूप से भारत 46 अन्य देशों की तुलना में प्रतिवादियों के लिए अधिक आकर्षक है जिन्हें मागोटेक्स की अन्य विनिर्माण इकाइयों द्वारा पहले से आपूर्ति की जा रही है तथा जो इस क्षेत्र के आस-पास हैं।

अ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

86. चूंकि किसी संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का कोई ज्ञात आयात नहीं है, इसलिए प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि क्या एडीडी हटाने पर पाटन की पुनरावृत्ति होने की आशंका है और यदि ऐसा होता है तो क्या घरेलू उद्योग को उससे क्षति होने की संभावना है। आवेदकों ने अपनी याचिका में पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना के साक्ष्य दिए हैं और जांच के दौरान उन्हें संपूरित किया है और यह अनुरोध किया है कि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों और रिकॉर्ड में साक्ष्य की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है। प्राधिकारी ने, धारा 9क(5), नियम 23 में निर्धारित अपेक्षाओं और नियमावली के अनुबंध-II(vii) और रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे संबंधी मापदंडों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की है। चूंकि वर्तमान जांच इस समय लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णयक समीक्षा जांच है और नियमावली के अन्तर्गत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटनरोधी शुल्क को लागू रखना आवश्यक है।

87. ऐसा कोई संभावना विश्लेषण करने की कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का उल्लेख है जिन पर विचार करना अपेक्षित है, अर्थात्;

- भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि दर जिससे काफी अधिक आयात की संभावना का पता चलता हो।
- निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि की संभावना, जो किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों में काफी पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाती हो।
- क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर अत्यधिक हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और उनसे आयातों के लिए मांग में और अधिक वृद्धि होने की संभावना होगी।
- वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।

88. प्राधिकारी ने, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एडीडी हटाने पर पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है और यदि हां तो क्या उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अलावा, प्राधिकारी विचार करते हैं कि उपर्युक्त मापदंडों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लागू करना अपेक्षित है कि पहले से एडीडी लागू था। अतः, प्राधिकारी ने उपर्युक्त मापदंडों पर विचार करते हुए जांच की है कि क्या एडीडी की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का काफी अधिक खतरा है।

क. **तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में पाटन**

89. घरेलू उद्योग ने यह दलील दी है कि संबद्ध उत्पादक अनेक तीसरे देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं और यह निर्यात पाटित कीमतों पर हैं। यद्यपि चीन के उत्पादकों से कोई उत्तर नहीं मिला है परंतु एकमात्र थाई उत्पादक ने उत्तर दिया है और संगत सूचना दी है। प्राधिकारी ने वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को संबद्ध देशों से निर्यात की जांच की है और यह निर्धारित किया है कि क्या ये निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमत पर हुए हैं। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को निर्यातों की मात्रा निर्धारित की है और पाटित और क्षतिकारी कीमत पर निर्यात की मात्रा निर्धारित की है। प्राधिकारी ने यह पता लगाने के लिए कि क्या निर्यातकों को भारतीय बाजार में प्रचलित कीमतों और उन कीमतों, जिन पर निर्यातक तीसरे देशों को बिक्री कर रहे हैं, के अनुसार भारतीय बाजार को पर्याप्त आकर्षण लगाने की संभावना है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ इन निर्यातों की तुलना भी की है। सारांश स्थिति निम्नानुसार है:

| विवरण | समग्र मात्रा | | | भारतीय खपत के संबंध में | | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------|--------|
| | ईक्यूआर के अनुसार | ट्रेड मैप डाटा के अनुसार | ईक्यूआर के अनुसार | ट्रेड मैप डाटा के अनुसार | | |
| | मैगोटेक्स | थाइलैंड | चीन | मैगोटेक्स | थाइलैंड | चीन |
| | (एमटी) | (एमटी) | (एमटी) | (%) | (%) | (%) |
| सामान्य मूल्य से नीचे तीसरे देशों को निर्यात की मात्रा | *** | *** | *** | 81.49% | 91.33% | 54.47% |
| एनआईपी के नीचे तीसरे देश के निर्यात की मात्रा | *** | *** | *** | 10.31% | 1.69% | 6.44% |
| भारत में प्रचलित बिक्री मूल्य से नीचे तीसरे देश के निर्यात की मात्रा | *** | *** | *** | 13.98% | 1.61% | 13.73% |

90. उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित देखा जा सकता है:

- निर्यातक द्वारा *** मीट्रिक टन निर्यात पाटन की गई कीमत पर है जो कुल भारतीय मांग का 81.49% है। निर्यातक की घोषित क्षमता *** मीट्रिक टन है। यह इंगित करता है कि लगभग 89% निर्यात पाटित कीमतों पर हैं और निर्यातक भारी नुकसान पर निर्यात कर रहे हैं।
- निर्यातकों द्वारा *** मीट्रिक टन निर्यात क्षतिकारक कीमत पर है। निर्यात की यह हानिकारक मात्रा कुल भारतीय मांग का 10.31% है।
- निर्यातक द्वारा *** मीट्रिक टन निर्यात उस कीमत से कम कीमत पर किया जा रहा है जिस पर भारतीय बाजार में माल बेचा जा रहा है। निर्यातकों को निर्यात की इस मात्रा को भारत में मोड़ने के लिए भारतीय बाजार आकर्षक लगेगा, खासकर जब यह घाटा कर रहा हो। निर्यात की यह कीमत आकर्षक मात्रा भारतीय मांग का लगभग 14% है।
- इस प्रकार यह देखा गया है कि निर्यातक पूरी दुनिया में अन्यथिक निर्यात उन्मुख और डंपिंग माल है। पाटित और क्षतिपूर्ण कीमतों पर भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। निर्यातक को भारी घाटा हो रहा है। पाटित, क्षतिपूर्ण और कीमत आकर्षक तीसरे देश का निर्यात भारतीय मांग के संबंध में महत्वपूर्ण है और घरेलू बाजार में व्यवधान पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, शुल्क समाप्त करने से पाटित और क्षतिपूर्ण कीमत पर भारत को निर्यात की भारी मात्रा होने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

ख. भारतीय बाजार में दिए गए कीमत प्रस्ताव

- आवेदकों ने चीनी उत्पादकों द्वारा कीमत की पेशकश के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। आवेदकों ने मैगोटॉक्स इंडिया द्वारा दिए गए कई मूल्य प्रस्तावों का उत्पादन किया है। कुछ मूल्य ऑफर मूल देश को थाइलैंड के रूप में दर्शाते हैं। जांच के दौरान, निदेशालय ने 10 कंपनियों से संपर्क किया, जिन्हें कथित तौर पर मैगोटॉक्स इंडिया से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 10 कंपनियों में से 5 कंपनियों ने निदेशालय को सूचित किया है कि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के लिए मैगोटॉक्स समूह द्वारा उनसे संपर्क किया गया है। यह भारत में संबद्ध वस्तुओं को बेचने के लिए मैगोटॉक्स ग्रुप के स्पष्ट इरादे को इंगित करता है। यह दोहराया जाता है कि निर्यातक द्वारा *** मीट्रिक टन निर्यात पाटित मूल्य पर है जो कुल भारतीय मांग का 81.49% है। निर्यातक की घोषित क्षमता *** मीट्रिक टन है। यह

इंगित करता है कि लगभग 89% निर्यात पाटित कीमतों पर है और निर्यातक भारी नुकसान पर निर्यात कर रहा है। निर्यातकों द्वारा निर्यात का *** मीट्रिक टन हानिकारक कीमत पर है। इसके अलावा, निर्यात की यह हानिकारक मात्रा कुल भारतीय मांग का 10.31% है। इसलिए यह देखा गया है कि इस बात की संभावना है कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, प्रतिवादी निर्यातक/उत्पादक भारतीय बाजार में पाटन शुरू कर देगा जिससे घरेलू उद्योग को थक्कि होगी।

93. इसके अलावा, प्राधिकारी ने मागोटेक्स थाइलैंड और आवेदकों द्वारा पहचाने गए अनेक उपभोक्ताओं को इन प्रस्तावों के ब्यौरे देने के लिए लिखा है। मागोटेक्स थाइलैंड को पूर्ववर्ती एसएसआर के बाद तीसरे देशों के बाजारों में गंवाए गए ऑर्डर, मालसूची, विकिसित बाजारों तथा उसकी संबंधित भारतीय कंपनी मागोटेक्स इंडिया को किए गए कीमत प्रस्तावों के ब्यौरे देने का निदेश दिया गया था। मागोटेक्स थाइलैंड ने कुछके प्रश्नों का उत्तर दिया और अन्य के संबंध में अपने पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने का दावा किया। इस पर निम्नानुसार विस्तार से विचार किया जा रहा है;
94. मागोटेक्स के इस दावे के संबंध में कि आवेदकों द्वारा प्रदत्त कीमत प्रस्तावों के संबंध में उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मागोटेक्स इंडिया के प्रस्तावों में “मागोटेक्स समूह” के रूप में प्रस्ताव स्पष्ट रूप से दर्शने वाली पर्याम सूचना है और इसमें भारतीय बाजार से उत्पाद को खरीदने या उससे थाइलैंड में उद्भव पर आधारित कोई कीमत प्रस्ताव नहीं है। मागोटेक्स थाइलैंड और मागोटेक्स इंडिया, दोनों ने सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा लिया था और मागोटेक्स इंडिया के प्रतिनिधि ने यह विवरण दिया कि बाजार में ऐसे अनेक प्रस्ताव थे। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मागोटेक्स इंडिया द्वारा दिए गए प्रस्ताव की भाषा मागोटेक्स के उत्पाद की आपूर्ति की ओर संकेत करती है।
95. मागोटेक्स थाइलैंड के इस वक्तव्य के संबंध में कि उसके पास मागोटेक्स इंडिया और मागोटेक्स इंडिया के पास उसका कोई नियंत्रण नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मागोटेक्स थाइलैंड ने एक “संबद्ध कंपनी” के रूप में मागोटेक्स इंडिया की पहचान की है। इसके अलावा, यद्यपि प्रश्नावली में मागोटेक्स इंडिया के बारे में सूचना अपेक्षित है, तथापि निर्यातकों ने बताया है कि पीओआई में आयातों की अनुपस्थिति के मद्देनजर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तथापि निर्यातक ने तीन श्रृंखलाएं बताई हैं और मागोटेक्स इंडिया के ज़रिए तथा बिक्री चैनल के रूप में मागोटेक्स इंडिया द्वारा सीधी खरीद और बिक्री की पहचान की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान अवधि के दौरान उत्पाद का स्वीकृत रूप से कोई आयात नहीं हुआ है और इसलिए प्राधिकारी को संभावना निर्धारित करना अपेक्षित है, जहां एडीडी हटाने पर संभावित आयातों का होना महत्वपूर्ण और संगत है। वितरण के संबंध और चैनल को देखते हुए, मागोटेक्स इंडिया के उत्तर संगत और आवश्यक थे। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद की उसकी प्रस्तावित कीमत और आपूर्ति के दावों के सत्यापन के लिए मागोटेक्स इंडिया के बारे में सूचना मांगी थी। यह इस तथ्य के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि मागोटेक्स इंडिया द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव मागोटेक्स समूह के बारे में काफी उल्लेख करते हैं। मागोटेक्स इंडिया ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि “अपने स्थापना कार्यकलाप के 100 वर्ष मनाते हुए..... मागोटेक्स ने ग्राइडिंग इंडिया के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है और500,000 एमटी से अधिक की विश्व-व्यापी क्षमता के साथ मागोटेक्स ने विश्व भर में अनेक विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने और विशिष्ट रूप से अनुकूल अलायं की व्यापक रेंज प्रदान करने के लिए एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड हासिल किया है और समेकित किया है....., क्योंकि हम प्रत्येक महाद्वीप में मौजूद एक विश्व-व्यापी समूह से संबंधित हैं, हम समय पर वस्तुओं की विधिवत् निकासी के साथ सही प्रेषकों सहित समय पर आपूर्ति करने के, सही निरीक्षण करने और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और मालभाड़ा लागत को ईष्टम बनाने के सर्वाधिक कारगर तरीके जानते हैं; अपने भली-भांति फैले विनिर्माण नेटवर्क के साथ..... अनुरोध करने पर उद्भव स्रोत को अनुकूल बनाया जा सकता है और आपकी अपेक्षाएं पूरी करने की योजना बनाई जा सकती है। हम भूगोल और राजनीतिक अस्थिरता पर ध्यान दिए बिना लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।” प्रतिवादी निर्यातक ने दावा किया है कि ये दोनों समूह कंपनियां एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करती हैं और इसलिए मागोटेक्स इंडिया संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकता है। तथापि, यह नोट किया गया है कि मागोटेक्स थाइलैंड ने मागोटेक्स इंडिया की एक संबद्ध

कंपनी के रूप में पहचान की है और तीन में से उन दो चैनलों की पहचान की है जिनमें मागोटेक्स इंडिया शामिल है। इसके अलावा, मागोटेक्स इंडिया के निदेशक ने सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा लिया और ऐसे वक्तव्य दिए जो मागोटेक्स इंडिया तक सीमित नहीं थे और मागोटेक्स थाइलैंड तक विस्तृत थे। यह भी देखा गया है कि मागोटेक्स इंडिया के प्रस्तावों में समूह का काफी उल्लेख किया जाता है और उसमें समूह के ब्यौरे, उनके 100 वर्ष के अनुभव, विश्व-व्यापी विनिर्माण नेटवर्क आदि का उल्लेख किया गया है। प्राधिकारी यह नहीं मानते हैं कि मागोटेक्स थाइलैंड, मागोटेक्स इंडिया से असंबद्ध होने का दावा कर सकता है। इसके अलावा, मागोटेक्स इंडिया द्वारा किए गए प्रस्तावों का तरीका और मागोटेक्स थाइलैंड द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर (एडीडी के कारण निर्यातों की गैर-मौजूदगी, एडीडी हटने पर आपूर्ति करने की इच्छा, सुनवाई में भागीदारी और सुनवाई के समय मौखिक रूप से दिए गए विवरणों आदि में बताते हुए) मागोटेक्स थाइलैंड को प्राधिकारी को संगत सूचना देने से मुक्त नहीं कर सकते हैं। चूंकि इन प्रश्नों का उद्देश्य एडीडी हटाने पर पाठन की संभावना का पता लगाना था, इसलिए सूचना को संगत आवश्यक माना गया था। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या बिक्री में शामिल संबंधित पक्षकार से कोई उत्तर मांगना प्राधिकारी की प्रक्रिया रही है। मागोटेक्स थाइलैंड ने मागोटेक्स इंडिया से संबंधित संगत सूचना नहीं दी है। अतः, प्राधिकारी रिकॉर्ड या अन्यथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना और दस्तावेजों पर आधारित तथ्यों को सिद्ध करने पर बाध्य हैं।

96. भारतीय उपभोक्ताओं को मागोटेक्स इंडिया से खरीद/कीमत के ब्यौरे, संबद्ध वस्तु के विनिर्माता के ब्यौरे देने तथा मागोटेक्स इंडिया और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्पाद में अंतर के ब्यौरे देने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी द्वारा दस उपभोक्ताओं की नीति में से पांच ने यह उत्तर दिया कि मागोटेक्स ने पीयूसी की बिक्री के लिए उनसे संपर्क किया था।
97. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को पढ़ा है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आरोपों का खंडन करने के लिए प्रतिवादी निर्यातक को अवसर दिया है और मागोटेक्स द्वारा बिक्री, खरीद और प्रस्तावों के ब्यौरे मांगे हैं परंतु निर्यातक द्वारा मांगी गई सूचना नहीं दी गई है। प्राधिकारी द्वारा संपर्क किए गए कुछ उपभोक्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि मागोटेक्स ने पीयूसी की बिक्री के लिए उनसे संपर्क किया है। अतः, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट करते हैं कि:
 - i. मागोटेक्स इंडिया भारत में मागोटेक्स थाइलैंड का बिक्री स्कंध है। घरेलू उद्योग ने मागोटेक्स इंडिया द्वारा भारतीय या थाई उत्पाद अपने बाजार को स्थापित करने के मद्देनजर प्रस्तुत करने की दलील इसलिए दी है ताकि वह एडीडी हटने तक भारी मात्रा में निर्यात कर सके। मागोटेक्स थाइलैंड ने स्पष्ट किया है कि उसने भारत में निर्मित उत्पाद की आपूर्ति की है। अपने प्रश्नावली के उत्तर में मागोटेक्स थाइलैंड ने एडीडी हटने पर उत्पाद का निर्यात करने का अपना इरादा भी बताया है।
 - ii. मागोटेक्स इंडिया द्वारा प्रस्तावित कीमतों में उत्पाद प्रकार प्रस्तुत मात्रा, कीमत आधार आदि सहित विस्तृत सूचना दी गई है।
 - iii. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि ये कीमतें एक सांकेतिक कीमत हैं जिन पर पाठनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में मैगोटॉक्स थाईलैंड भारत को निर्यात कर सकता है।
98. घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि चीन और थाइलैंड के उत्पादकों के पास भारी मुक्त रूप से निपटान योग्य उत्पादन क्षमता है। निर्यात और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की विस्तार से जांच की गई है। निम्नलिखित अवलोकन किया गया है:
 - i. यद्यपि घरेलू उद्योग का तर्क है कि थाई उत्पादक के पास 1,40,000 एमटी की उत्पादन क्षमता है परंतु मागोटेक्स थाइलैंड द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में उनकी क्षमता *** एमटी दर्शाई गई है।

ii. यद्यपि घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान थाइलैंड से 93,217 एमटी की कुल निर्यात मात्रा बताई है परंतु मागोटेक्स द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात मात्रा *** एमटी दर्शाई गई है।

iii. थाइलैंड के उत्पादक के पास वर्तमान पीओआई के दौरान *** प्रतिशत क्षमता उपयोग है।

99. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अपने अनुरोध में मागोटेक्स ने बताया है कि चूंकि मूल जांच के बाजार जहां बिक्री में वृद्धि हुई है, मध्य पूर्व, यूरोप, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका हैं। इसके अलावा, चूंकि पूर्ववर्ती जांच से दक्षिण अमेरिका और आस्ट्रेलिया में बिक्री में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि निर्यातक ने यह बताया है कि उसने वैश्विक रूप से बड़ी संख्या में बाजार बना लिए हैं परंतु उसने अपने इक्यूआर में यह भी बताया है कि वैश्विक बाजार में उसकी समूची बिक्री ऑन स्पाट आधार पर होती हैं। इस प्रकार, इन बाजारों को ऑन स्पॉट बाजार के रूप में विकसित किया गया है और निर्यातक ने इन बाजारों हेतु आपूर्ति के लिए क्षमताओं के किसी हिस्से की वचनबद्धता नहीं की है। अतः, घरेलू खपत (*** एमटी से कम की) को छोड़कर निर्यातक की संपूर्ण क्षमता भारत सहित किसी भी वैश्विक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह देखा गया है कि निर्यातक की 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता किसी बाजार के लिए मुक्त रूप से निपटान योग्य है।

100. जहां तक चीन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने चीन की क्षमता और मांग का प्रमाण दिया है। हालांकि, सबूत जांच की अवधि से 8 साल पहले के हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह साक्ष्य हाल का नहीं है और यह स्थापित करने के लिए जांच की अवधि के करीब है कि चीनी उत्पादकों के पास उनके पास मुक्त रूप से प्रयोज्य उत्पादन क्षमता काफी अधिक है।

101. थाइलैंड में प्रतिवादी निर्यातक द्वारा यथा-प्रस्तुत संबद्ध वस्तु की क्षमता, उत्पादन और मांग निम्नानुसार है:

| विवरण | सूनिट | थाइलैंड |
|---|-------|----------|
| क्षमता | एमटी | *** |
| उत्पादन – पीयूसी | एमटी | *** |
| उत्पादन – एनपीयूसी | एमटी | *** |
| अप्रयुक्त क्षमता | एमटी | *** |
| मांग | एमटी | *** |
| मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता | एमटी | *** |
| भारत में मांग | एमटी | 1,01,841 |
| भारतीय मांग के प्रतिशत में मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता | % | 113% |
| भारतीय मांग के प्रतिशत में अधिशेष क्षमता | % | 18% |

102. तथापि, मागोटेक्स थाइलैंड ने अपनी क्षमता, उत्पादन लागत और बिक्री के संबंध में प्रश्नावली के अपने उत्तर में प्रस्तुत सूचना के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं दिया है। प्राधिकारी ने उस सूचना के आधार पर तथ्य सिद्ध किए हैं और उनके पास उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों पर विचार किया है।

103. इस प्रकार, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि थाइलैंड में काफी अधिक अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा उनके तीसरे देश के निर्यातों को भारत में भेजे जाने की आशंका है।

I. भारतीय बाजार की आकर्षकता

104. घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि भारतीय बाजार चीन के उत्पादकों के लिए आकर्षक है। मागोटेक्स थाइलैंड का प्रश्नावली का उत्तर दर्शाता है कि कंपनी ने पिछले दस वर्षों के दौरान 70 के लगभग बाजार विकसित किए हैं। इसके अलावा, मागोटेक्स समूह की पांच देशों में उत्पादन सुविधाएं हैं। मागोटेक्स थाइलैंड के लिए इन कारणों से भारतीय बाजार सर्वाधिक आकर्षक है (क) भारत में बढ़ी हुई मांग (ख) कंपनी द्वारा विकसित अन्य बाजारों की तुलना में थाइलैंड से निकटता (ग) भारत में बिक्री स्कंध की मौजूदगी, (घ) मागोटेक्स इंडिया के वर्तमान व्यापार कार्यकलाप। इसके अलावा, मागोटेक्स थाइलैंड ने अपने संगत भाग में प्रश्नावली के निम्नलिखित उत्तर बताए हैं:

- क. कंपनी विगत 10 वर्षों से लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को हटाने के अधीन निकट भविष्य में भारत को पीयूसी का निर्यात करने का इरादा रखती है।
- ख. कंपनी उत्पादन क्षमता, घरेलू बाजार पोतलदानों और अन्य बाजार (भारत से इतर) को निर्यातों में किसी परिवर्तन की उम्मीद नहीं करती है। तथापि, ऐसी आशा है कि कंपनी को भारतीय उपभोक्ताओं से कुछ ऑर्डर प्राप्त होंगे और उत्पादन में उतनी वृद्धि की जाएगी।
- ग. कंपनी के पास किसी उपभोक्ता के साथ कोई दीर्घकालिक आपूर्ति संविदा नहीं है। सभी निर्यात ऑन स्पॉट बिक्रियां हैं।

ii. मालसूची

105. मागोटेक्स थाइलैंड ने *** एमटी (31 मार्च, 2022 के अनुसार) मानकीकृत उत्पादों की मालसूची की सूचना दी है। कंपनी ने यह भी बताया है कि गैर-मानकीकृत उत्पाद ऑर्डरों के तहत विनिर्मित और आपूर्ति किए जाते हैं जबकि मानकीकृत उत्पादों को मालसूची से आपूर्ति किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और निर्यातकों, दोनों ने बताया है कि उत्पादन का काफी अधिक हिस्सा विशिष्ट ऑर्डरों के अधीन होता है। इन परिस्थितियों में, मानकीकृत उत्पादों की *** एमटी की मालसूची भारत में मानकीकृत उत्पाद के लिए उपलब्ध मांग को ध्यान में रखते हुए काफी अधिक है। यद्यपि सकल आधार पर भी मानकीकृत और गैर-मानकीकृत उत्पादों की मांग को अलग करने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि *** एमटी की मालसूची भारत में लगभग एक माह की खपत के बराबर है और इसलिए काफी अधिक है।

106. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि घरेलू उद्योग संभावित आयात की मात्रा की सीमा तक अपनी घरेलू बिक्री में कमी करता है तो उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ेगा। वैकल्पिक रूप से, यदि घरेलू उद्योग मैगोटॉक्स थाईलैंड के तीसरे देश के निर्यात मूल्य से मेल खाता है और आयात को रोकता है, तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता फिर से वित्तीय घाटे, नकद घाटे और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न की स्थिति में आ सकती है। इस प्रकार, दोनों स्थितियों में, घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल का नुकसान होने की संभावना है, यदि वर्तमान शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है।

107. चीन के उत्पादकों द्वारा रखी गई मालसूचियों के संबंध में घरेलू उद्योग ने कोई सूचना नहीं दी है।

संभावना संबंधी निष्कर्ष

108. ऊपर यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिए गए हैं कि थाइलैंड के विश्व पाटनरोधी शुल्क हटने पर पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना है। चीन के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त साक्ष्य संभावना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

ट. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

109. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. क्षति अवधि में कोविड-19 के प्रभाव के आलोक में शुल्क लागू करने से प्रभुत्व की स्थिति और एकाधिकारी बाजार सृजित होगा जिससे वस्तुओं की लागत गैर-किफायती और अत्यधिक हो जाएगी।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध कि संबद्ध आयातक कैसे उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में नहीं रखते हैं, अवैध है और तथ्यों से परे है। प्राधिकारी द्वारा इसकी अनदेखी की जानी चाहिए।
- ग. मागोटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत में उपभोक्ताओं की पसंद है। उन्हें अन्य गैर-सहयोगी घरेलू विनिर्माताओं से संविदा के अन्तर्गत विनिर्मित पीयूसी प्राप्त होती हैं। यह अवैध नहीं है, या नियमों की प्रवंचना नहीं है।
- घ. शुल्क जारी रखने से आवेदकों के एकाधिकारी रवैये के अधीन भारतीय उपभोक्ताओं को क्षति होगी।

ट.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

110. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. वर्तमान जांच में आयातकों/प्रयोक्ताओं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार भागीदारी नहीं करने से पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने से भारतीय उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ख. अन्य घरेलू विनिर्माताओं से शुल्क को जारी रखने की मांग करते हुए समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं ताकि संबद्ध देशों से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
- ग. लागू शुल्क की अवधि घरेलू उद्योग के वित्तीय आंकड़े, क्षति अवधि में कीमत मापदंडों में गिरावट दर्शाती है कि घरेलू उद्योग बाजार में एकाधिकार में शामिल नहीं है या उसका प्रयास नहीं कर रहा है।
- घ. शुल्क किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना पिछले दस वर्षों से लागू है। उपभोक्ताओं पर प्रभाव 0.02 प्रतिशत – 0.03 प्रतिशत के स्तर पर नगण्य हैं।
- ड. घरेलू उद्योग के पास देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक क्षमताएं हैं और संबद्ध आयात पूर्णतः अनावश्यक हैं। भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की मांग – आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है।
- च. शुल्क हटाने से सस्ते आयातों की बाढ़ आ जाएगी जो मौजूदा घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू विनिर्माताओं को संबद्ध वस्तु से बाहर कर देगी।
- छ. इस दलील के संबंध में कि मागोटेक्स इंडिया उपभोक्ताओं को पसंद है, यह अनुरोध किया गया है कि संबंधित कंपनी वर्तमान जांच में सहयोग करने में विफल रही है। इसके अलावा, इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य/समर्थन नहीं दिया गया है।
- ज. मागोटेक्स ने बाजार में स्वयं को पुनः स्थापित करने के अपने प्रयास में उपभोक्ताओं के हित की अनदेखी करना जारी रखा है।

झ. इस दलील के संबंध में कि कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है और शुल्क से एकाधिकार हो जाएगा, यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा कोई संगत कारक मात्रा या मौजूदगी संबंधी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा बाजार में अन्य घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि कोई प्रभुत्व या एकाधिकारी बाजार सुजित न हो।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभावों सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना देने हेतु उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी विहित की थी। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के प्रति स्थापनीयता स्रोत बदलने की उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, और उन कारकों संबंधी सूचना मांगी है जिससे पाटनरोधी शुल्क लागू होने से उत्पन्न नई स्थिति में समायोजन में शीघ्रता या देरी होने की संभावना है। विचाराधीन उत्पाद के किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने जांच शुरूआत अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है या प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
112. प्राधिकारी ने आर्थिक वित्त संबंधी एक प्रश्नावली विहित की थी जिसे इस समीक्षा जांच के सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। केवल घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली में मांगी गई सूचना दी है। आवेदक ने अपनी आर्थिक हित प्रश्नावली में घरेलू उद्योग तथा प्रयोक्ता उद्योग से संबंधित सूचना दी है।
113. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से संबद्ध वस्तुओं तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्रयोग से निर्मित अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत स्तर निर्धारित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपाय लागू होने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय को जारी रखने से घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी जो संबद्ध देश से कम कीमत के संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप हो रही है तथा संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता में मदद मिलेगी।
114. घरेलू उद्योग के एकाधिकारी व्यवहार के मुद्दे पर यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन को समाप्त करना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है या क्षति होने की संभावना है (एसएसआर के मामले में) और भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल करना है, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी नियमावली से यह ज्ञात नहीं होता है कि कोई एकाधिकारी कंपनी अनुचित आयातों के विरुद्ध प्राधिकारी से कार्यवाही हेतु अनुरोध करने के लिए निषिद्ध है। वर्तमान मामले में भारत में विचाराधीन उत्पाद के 11 उत्पादक हैं ऐसी स्थिति में एकाधिकारी प्रक्रिया का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ये कंपनियां घरेलू बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई में उत्पाद के कोई ज्ञात आयात नहीं थे और क्षति अवधि में आयात की मात्रा कम थी। उत्पाद की 99 प्रतिशत से अधिक मांग भारतीय उद्योग द्वारा पूरी की जाती है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग द्वारा किसी एकाधिकारी नीति या कार्य का कोई साक्षात्कृत मामला नहीं था। इसके अलावा, वर्तमान क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूँजी पर आय में गिरावट आई और संपूर्ण क्षति अवधि में कम रहे हैं। यदि घरेलू उद्योग एकाधिकारी स्थिति में होता या घरेलू उद्योग ने एकाधिकारी नीति अपनाई होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती। यह भी स्पष्ट है कि आयातों की गैर-मौजूदगी के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम रही है और भारतीय बाजार में भारतीय उद्योग का अधिकांशतः पूरा हिस्सा रहा है।

115. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पाद का प्रयोक्ता उद्योग मुख्यतः देश में खनन और सीमेंट उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग ने अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव संबंधी सूचना दी है। प्राधिकारी ने अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट किया है जो लगभग 0.02 प्रतिशत – 0.03 प्रतिशत है। जैसा नीचे देखा जा सकता है। यह एक सैद्धांतिक स्थिति है जहां भारतीय उद्योग एडीडी के बराबर अपनी कीमतों में वृद्धि करता है:

| विवरण | यूओएम | सीमेंट | खनन |
|--|-------------|---------|---------|
| तैयार उत्पाद की कीमत | रु./एमटी | 7,000 | 70,000 |
| तैयार उत्पाद का उत्पादन | एमटी | 1050000 | 2000000 |
| जीएम बाल की कुल खपत | एमटी | 53 | 1,600 |
| तैयार उत्पाद के प्रति एमटी जीएम बाल की खपत | एमटी | 0.00005 | 0.00080 |
| जीएम बाल पर पाटनरोधी शुल्क | आईएनआर/एमटी | 29,168 | 29,168 |
| प्रभाव | आईएनआर/एमटी | 1.46 | 23.32 |
| % प्रभाव | %/एमटी | 0.021% | 0.033% |

116. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की अनुपलब्धता नहीं होगी। यह भी नोट किया जाता है कि देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं हैं और घरेलू उद्योग के पास समूची भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संपूर्ण क्षति अवधि में उत्पाद का व्यावहारिक रूप से कोई आयात नहीं हुआ है और उत्पाद की 99 प्रतिशत से अधिक मांग भारतीय उद्योग द्वारा पूरी की गई थी। किसी भी उपभोक्ता ने भागीदारी नहीं की है और सामग्री की कमी की शिकायत नहीं की है। इसके विपरीत, कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि वे घरेलू उत्पादकों से सामग्री लेकर संतुष्ट हैं।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

117. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- प्राधिकारी वेलकास्ट स्टील लिमिटेड के प्रपत्र एक्स में प्राधिकार की गैर-मौजूदगी संबंधी आपत्ति का समाधान करने में विफल रहे हैं।
- प्राधिकारी ने उन चार घरेलू उत्पादकों का प्रकटन नहीं किया है जिन्होंने आवेदन का समर्थन किया है।
- नियम 2(ग) में विदेशी उत्पादक की घरेलू संबंधित कंपनी के लिए जांच में अनिवार्यता भागीदारी करना अपेक्षित नहीं है जिससे विदेशी उत्पादक के विरुद्ध प्रतिकूल अर्थ लगाया जाएगा। अतः, मागोटेक्स को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं करना व्यापार सूचना 11/2018 की प्रवंचना नहीं है।

घ. निर्यातक द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे घरेलू उद्योग के दावों की प्रतिलिपि है। अतः निर्यातक पर अत्यधिक गोपनीयता का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

उ. इस विवरण में विरोधाभास है कि क्षति की जांच घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है और यह अवलोकन है कि घरेलू उद्योग को विदेशी बाजार में नुकसान हुआ है जिससे उनका उत्पादन और क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ है।

च. प्राधिकारी को तीसरे देश के बाजारों में गंवाए गए आदेशों के ब्यौरे नहीं मांगने चाहिए थे।

छ. मागोटेक्स इंडिया की प्रस्ताव कीमत निर्धारित पहुंच मूल्य के लगभग आस-पास नहीं हो सकती है क्योंकि मागोटेक्स इंडिया द्वारा बेची गई मात्राएं घरेलू रूप से विनिर्मित हैं और न्यूनतम लाभ पर बेची गई।

ज. घरेलू उद्योग मनगढ़त बीजकों/प्रस्तावों पर भरोसा कर रहा है जिन्हें सत्यापित और उनकी जांच करनी होगी।

झ. मागोटेक्स इंडिया द्वारा व्यापार की गई मात्रा घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और बेची गई मात्रा की तुलना में बहुत कम है और पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

ञ. प्राधिकारी ने इस निर्विवाद तथ्य कि मागोटेक्स ने निर्यातक से पीयूसी का आयात नहीं किया है, के बजाए मान्यताओं और अनुमानों पर भरोसा किया है।

ट. मागोटेक्स की भागीदारी के लिए मांग त्रुटिपूर्ण है क्योंकि (i) एक वितरण चैनल होने के बावजूद मागोटेक्स इंडिया ने पीओआई के दौरान आयात नहीं किया है (ii) मागोटेक्स समूह में अनेक कंपनियां शामिल हैं, मागोटेक्स इंडिया की भागीदारी की मांग करने का अर्थ यह होगा कि मागोटेक्स की सभी समूह कंपनियों को वर्तमान जांच में भागीदारी करने के लिए बाध्य किया जाए (iii) मागोटेक्स इंडिया द्वारा शुल्क के प्रभाव को हटाने के लिए दिया गया आश्वासन व्यर्थ प्रताप है क्योंकि इसके बावजूद निर्यातक को क्रेता नहीं मिल सके थे (iv) मागोटेक्स इंडिया संविदा के अन्तर्गत स्थानीय रूप से तीसरे पथकार द्वारा विनिर्मित उत्पादों की बिक्री कर रहा है जो अवैध नहीं है और पाटन तथा क्षति की संभावना या पुनरावृत्ति के निर्धारण में अप्रासंगिक है।

ठ. एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड ने उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप संकेतकों में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग दुर्भावनापूर्ण और एकाधिकारी व्यवहार से ग्रस्त है।

ड. घरेलू उद्योग चिरस्थाई पाटनरोधी शुल्क की मांग कर रहा है जो पाटनरोधी शुल्क के उद्देश्य के विरुद्ध है क्योंकि 0 आयात हुए हैं और 10 लंबे वर्षों के बाद आगे संरक्षण की मांग करने का कोई न्याय-संगत कारण नहीं है।

ढ. घरेलू उद्योग मागोटेक्स से प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके भारतीय प्रयोक्ता का शोषण कर रहा है।

ण. मैगोटॉक्स इंडिया, मैगोटॉक्स की एक समूह इकाई है, जिसमें से मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड भी ऐसी ही एक इकाई है। केवल इसलिए कि मैगोटॉक्स इंडिया एक ही मैगोटॉक्स समूह से संबंधित है और इसलिए, मैगोटॉक्स इंडिया को भाग लेने की आवश्यकता है, तो मैगोटॉक्स की सभी समूह कंपनियों को भी वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

ठ.2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

118. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. मागोटेक्स थाइलैंड द्वारा प्रकटन के दिन किए गए अनुरोध देरी से किए गए हैं। पूरी जांच के दौरान उन्होंने प्राधिकारी, नियमावली और कानून द्वारा विहित समय सीमाओं की पूरी तरह से अनदेखी की है।

ख. प्रतिवादी प्रश्नावली के अनुसार विहित सूचना देने, प्रश्नावली का सार्थक अगोपनीय अंश परिचालित करने, सत्यापन हेतु संगत दस्तावेज देने आदि में विफल रहे हैं। मागोटेक्स थाइलैंड जांच के दौरान सहयोग करने में विफल रहा है।

ग. अनुरोधों का अगोपनीय अंश 5 अप्रैल, 2023 को देरी से प्रस्तुत किया गया और घरेलू उद्योग को परिचालित नहीं हुआ था। घरेलू उद्योग इन अनुरोधों की विषय-वस्तु से अनभिज्ञ है।

घ. निर्यातक की प्रश्नावली में सभी संबंधित कंपनियों द्वारा सूचना देने का अनुदेश है। संबंधित कंपनी मागोटेक्स इंडिया, जो एक आयातक है द्वारा भागीदारी नहीं करना, मागोटेक्स थाइलैंड के बिक्री और विपणन कार्यालय ने क्षति अवधि में घरेलू बिक्रियां की हैं और पाटित तथा क्षतिकारी कीमत पर संबद्ध वस्तु उपभोक्ताओं को बेची है और जांच में अत्यधिक बाधा डाली है।

ड. मागोटेक्स इंडिया के असहयोग के कारण प्राधिकारी वर्तमान जांच में खरीद, प्रचालन, शामिल यूनिटों और वितरण की श्रृंखला के व्यौरों का सार्थक रूप से विश्लेषण नहीं कर पाए हैं।

च. मागोटेक्स थाइलैंड और इंडिया, मागोटेक्स समूह द्वारा नियंत्रित हैं, संबद्ध हैं और उनके साझे निदेशक हैं। वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए सौदों के व्यौरों में इन कंपनियों के बीच बिक्री और वस्तु की खरीद तथा प्रबंधन परामर्श का खुलासा किया गया है।

छ. मागोटेक्स इंडिया द्वारा किए गए प्रस्तावों पर निर्यात कीमत की गणना प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार की गई है। इस नीति को डेनमार्क से कैटेलिस्ट, ईयू, सिंगापुर, थाइलैंड, जापान, ब्राजील और कोरिया गणराज्य से पीआईबी तथा आस्ट्रिया, चेक गणराज्य, रूस और यूक्रेन से सीमलेस ट्यूब्स सहित विभिन्न क्षेत्राधिकारों में जांचों में अपनाई गई है। कतर से कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 की पाटनरोधी जांच का उल्लेख और उस पर भरोसा किया गया है।

ज. मागोटोक्स समूह एक वैश्विक एकाधिकार बनाना चाहता है, जैसा कि व्यापार उपचारात्मक उपायों के इतिहास से देखा जा सकता है; तीसरे देश के बाजार में पाटित उत्पादों को बेचना और शुल्क लागू होने के समय मागोटेक्स थाइलैंड को नुकसान हुआ है।

झ. घरेलू उद्योग तथा घरेलू उत्पादकों, जो एमएसएमई हैं, के संरक्षण के लिए 10 वर्ष के बाद मागोटेक्स थाइलैंड द्वारा प्राप्त रियायतों और लाभों के प्रभाव का सामना करने के लिए शुल्क जारी रखा जाना चाहिए; मागोटेक्स इंडिया द्वारा प्रस्तुत कीमत के अनुसार, प्रतिवादी के पास उपलब्ध मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता और मालसूची तथा तीसरे देश को पाटन के अनुसार शुल्क को जारी रहना चाहिए।

ज. मागोटेक्स पर लागू शुल्क पर विचार करते हुए अंतिम उपभोक्ता पर शुल्क के प्रभाव की पुनःगणना की गई है। यह 0.009-0.014 प्रतिशत है और नगण्य तथा मामूली रहना जारी है।

ट. भारत में उपभोक्ताओं को उचित कीमत मिल रही है क्योंकि घरेलू उद्योग ने लागत में वृद्धि के अनुपात में बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं की है और घरेलू उद्योग के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

119. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां दोहराव हैं, जिनका प्रकटन विवरण के संगत पैराओं में उपयुक्त और पर्याप्त रूप से जांच की गई है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली बार की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है:

120. इस दलील के संबंध में कि वेलकास्ट स्टील को विहित प्रपत्र में प्राधिकार नहीं दिया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वेलकास्ट स्टील एआईए इंजीनियरिंग के पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी है। चूंकि मूल कंपनी पीयूसी के उत्पादन में शामिल है और उसने वेलकास्ट द्वारा उत्पादित सामग्री बेची है, इसलिए प्राधिकारी ने सूचना को स्वीकार किया है। किसी भी तरह प्राधिकारी को वेलकास्ट से प्रपत्र एक्स प्राप्त हुआ है और उन्होंने सूचना का आगे सत्यापन किया है तथा सूचना और साक्ष्य की पर्याप्तता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा विहित प्राधिकार और प्रमाण-पत्र प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए हैं और उनसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के हितों के विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं हुआ है।

121. जहां तक अन्य घरेलू उत्पादकों के नामों का संबंध है जिन्होंने आवेदन का समर्थन किया है, प्रतिवादी निर्यातक ने दस्तावेज के अगोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के निर्धारित समय के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर कोई टिप्पणी नहीं की। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि समान नाम के प्रकटीकरण से पार्टी के हित पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकरण ने इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और संतुष्ट होने पर प्राधिकरण ने पार्टी के नाम पर गोपनीयता की अनुमति दी है। प्राधिकरण इस संबंध में नोट करता है कि यह असामान्य नहीं है कि संबंधित पक्षों के नाम भी गोपनीय होते हैं, विशेष रूप से जब विरोधी पक्षों के परस्पर विरोधी व्यावसायिक हित शामिल होते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग स्वयं नियम 5(3) के अनुसार स्थायी आवश्यकता को पूरा करता है। इसलिए, समर्थक के रूप में अन्य घरेलू उत्पादकों की आवश्यकता वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है।

122. जहां तक इस विवाद का संबंध है कि मैगोटॉक्स इंडिया को वर्तमान जांच में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैगोटॉक्स थाईलैंड ने क्षति अवधि के दौरान निर्विवाद रूप से सामग्री बेची है। केवल जांच की अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ है। इसके अलावा, मैगोटॉक्स थाईलैंड ने स्वयं मैगोटॉक्स इंडिया को अपने बिक्री चैनलों में से एक के रूप में पहचाना है। वर्तमान जांच का दायरा इस शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को इंपर्सिंग और परिणामी क्षति की संभावना का पता लगाने के लिए है। ऐसी स्थिति में, अपनाया गया विक्रय चैनल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही कुछ मूल्य प्रस्ताव थाईलैंड के रूप में माल की उत्पत्ति का देश दिखाते हैं। मैगोटॉक्स इंडिया ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया है। यदि मैगोटॉक्स इंडिया वस्तुतः सुनवाई में शामिल हुआ, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि वर्तमान जांच में पार्टी की कोई दिलचस्पी नहीं है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां याचिकाकर्ताओं ने मैगोटॉक्स इंडिया द्वारा महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों का विरोध किया है और उसे उस समय भी स्वीकार किया गया है। सुनने का।

123. घरेलू और निर्यात बाजार के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन विश्लेषण में स्पष्ट विरोधाभास के बारे में यह बताया गया है कि क्षति जांच केवल घरेलू बाजार में बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन तक सीमित है। प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध विश्लेषण और संभावना के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन की जांच अलग से की है। निर्यात निष्पादन और निर्यात बाजारों में घरेलू उद्योग द्वारा गंवाए गए या प्राप्त बाजार की जांच केवल इन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात की प्रवृत्ति से संबंधित है।

124. जहां तक इस कथन का संबंध है कि मैगोटॉक्स इंडिया ने जांच की अवधि के दौरान निर्यातक से पीयूसी का आयात नहीं किया है, प्राधिकारी ने यह नहीं माना है कि मैगोटॉक्स थाईलैंड ने जांच की अवधि के दौरान मैगोटॉक्स इंडिया को सामग्री बेची है। प्राधिकारी ने माना है कि थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है। तथापि, ऐसी स्थिति में जहां जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ था, नियमों के अनुसार प्राधिकारी को पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना का पता लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, क्षति अवधि के दौरान मैगोटॉक्स थाईलैंड द्वारा निर्यात किए गए थे। प्राधिकारी ने शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी सूचनाओं और साक्ष्यों पर विचार किया है।

125. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मैगोटॉक्स इंडिया की प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं थी, प्राधिकारी ने मैगोटॉक्स थाईलैंड, घरेलू उद्योग और अन्य पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की है और उनका मानना है कि मैगोटॉक्स

इंडिया का जवाब वर्तमान मामले के लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक था क्योंकि स्वयं मैगोटॉक्स थाईलैंड ने खुद ही इसका जवाब दिया है। भारत को निर्यात के लिए एक वितरण चैनल के रूप में मैगोटॉक्स इंडिया की पहचान की। प्राधिकरण ने यह नहीं बताया है कि मैगोटॉक्स थाईलैंड की सभी समूह संस्थाओं को प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करना चाहिए था। चूंकि जांच मैगोटॉक्स थाईलैंड द्वारा निर्यात से संबंधित है, जिस तरीके से मैगोटॉक्स थाईलैंड भारत को उत्पाद का निर्यात करेगा, वह संभावना निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो जाता है। हालांकि, एक सैद्धांतिक स्थिति में जहां मैगोटॉक्स थाईलैंड ने अपनी एक या अधिक वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से उत्पाद का निर्यात किया होगा, प्राधिकरण को उन संस्थाओं से प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। हालांकि, मैगोटॉक्स थाईलैंड ने वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए अन्य वैश्विक संस्थाओं की पहचान नहीं की है और इसलिए प्राधिकरण ने मैगोटॉक्स थाईलैंड की अन्य समूह कंपनियों से प्रतिक्रिया की मांग नहीं की है।

126. आवेदकों द्वारा यह दावा किया गया है कि मैगोटॉक्स इंडिया ने अपने ग्राहकों को शुल्क के प्रभाव को दूर करने का आव्वासन दिया है। निर्यातक/उत्पादक ने कहा है कि आवेदकों का यह दावा केवल बयानबाजी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क के प्रभाव को दूर करने के लिए मैगोटॉक्स इंडिया द्वारा दिए गए आव्वासन के संबंध में आवेदकों के दावे के बावजूद, मैगोटॉक्स थाईलैंड ने स्वयं कहा है कि वह शुल्क वापस लेने की स्थिति में कुछ सामग्री की आपूर्ति करेगा।
127. उत्पादन क्षमता, उत्पादन, घरेलू बाजार शिपमेंट्स, भारत और अन्य बाजारों को निर्यात, या भविष्य में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से संबंधित सूची पर शुल्क को रद्द करने के प्रभाव पर प्रतिक्रिया मांगने वाले सवाल के जवाब में मैगोटॉक्स थाईलैंड ने अपने प्रश्नावली के जवाब में कहा है कि "कंपनी उत्पादन क्षमता, घरेलू बाजार के शिपमेंट और अन्य बाजारों (भारत के अलावा) में निर्यात में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं करती है। हालांकि, उम्मीद है कि कंपनी को भारतीय ग्राहकों से कुछ ऑर्डर मिलेंगे और उस हद तक उत्पादन बढ़ सकता है।" मैगोटॉक्स थाईलैंड ने स्वीकार किया कि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में वे भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। यह पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का संकेत है।
128. जहां तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आर्थिक प्रदर्शन पर इसके प्रभाव का संबंध है, प्राधिकरण नोट करता है कि एआईए की उत्पादन लागत में वृद्धि को क्षमता में वृद्धि के साथ सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसकी मुख्य वजह कम्ब्रे माल की लागत में बढ़ोतरी है। वास्तव में, जिस संयंत्र में उत्पादन क्षमता का विस्तार किया गया है, उसकी रूपांतरण लागत उस संयंत्र की तुलना में कम है, जिसने क्षमता का विस्तार नहीं किया।
129. याचिकाकर्ता द्वारा एकाधिकारी व्यवहार के आरोप के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास भारतीय बाजार में अधिकांश हिस्सा नहीं है। वास्तव में, भारतीय बाजार में अधिकांश हिस्सा एमएसएमई क्षेत्र का है जिसमें 11 कंपनियां हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने मूल जांच अर्थात् 2010 से उत्पादन और खपत में भारतीय उद्योग के हिस्से का विश्लेषण किया है। जैसा नीचे देखा गया है, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में एकाधिकारी स्थिति में नहीं है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क ने भारत में उत्पादन और खपत में एमएसएमई का हिस्सा बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है।

| | मूल जांच | प्रथम एसएसआर | वर्तमान एसएसआर |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| जांच की अवधि | जन.-दिस. 2010 | अप्रैल '16- मार्च'17 | अप्रैल '21- मार्च'22 |
| अन्य भारतीय उत्पादक (एमएसएमई) | | | |
| खपत में हिस्सा | 21% | 47% | 58% |
| उत्पादन में हिस्सा | 10% | 12% | 21% |

130. हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि आगे सुरक्षा की मांग करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं हो सकता है क्योंकि शुल्क पहले से ही 10 वर्षों से लागू थे, प्राधिकरण नोट करता है कि नियम शुल्क की अवधि को बढ़ाए जाने की संख्या को सीमित नहीं करते हैं। शुल्क की सिफारिश डंपिंग, क्षति और डंपिंग के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और घरेलू उद्योग को क्षति को ध्यान में रखते हुए की गई है। इन कारकों का इस अंतिम निष्कर्षों के उपयुक्त खंडों में विश्लेषण किया गया है।

ड. निष्कर्ष और सिफारिशें

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई तथा घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन तथा क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना के पहलुओं संबंधी सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया।

132. अनुशंसित एंटी-डंपिंग शुल्क घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को कम नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय उपभोक्ता घरेलू उत्पादकों, चीन और अन्य बाजारों से सामग्री प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

133. पिछले 10 वर्षों से उत्पाद पर लागू शुल्क ने घरेलू उद्योग की समान अवसर वाले बाजार में प्रचालन करने में मदद की है। यह भी दलील दी गई है कि उपभोक्ताओं पर पिछले 10 वर्षों से लागू एडीडी के किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है। बताए इसके, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है और यह बताते हुए उपभोक्ताओं के पत्र प्रस्तुत किए हैं कि उपभोक्ताओं को घरेलू उद्योग के उत्पादों के प्रयोग से लाभ हुआ है और लागत में बचत हुई है।

134. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी की राय है कि थाईलैंड से आयातों के संबंध में इस उपाय को विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने वर्ष 2019-2021 के लिए मैगोटॉक्स थाईलैंड की वार्षिक रिपोर्ट के सार के रूप में प्राधिकरण के समक्ष रखे गए साक्ष्यों को नोट किया है। यह देखा गया है कि कंपनी ने उत्पादन का लगभग 95% निर्यात करने के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए वित्तीय घाटे की सूचना दी है। प्राधिकरण की राय है कि कंपनी अन्य वैश्विक बाजारों में अच्छी कीमत पाने में सक्षम नहीं है और भारत जैसे लाभदायक बाजार की तलाश कर रही है।

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैगोटॉक्स थाईलैंड संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का 80 % से अधिक का निर्यात तीसरे देशों को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर कर रहा है। यह मैगोटॉक्स थाईलैंड के व्यवहार पैटर्न को दर्शाता है। इस बात की पूरी संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने पर वे भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर सकते हैं जिनका वर्तमान में तीसरे देशों को निर्यात किया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

136. घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों की क्षमता सामूहिक रूप से निर्यात का लेखा-जोखा रखने के बाद भी घरेलू मांग को पूरा कर सकती है। अतः किसी भी मात्रा का आयात घरेलू उत्पादकों की क्षमता से अतिरिक्त होगा। यदि आयातों को क्षतिपूर्ण कीमत पर पाटित किया जाता है तो घरेलू उत्पादकों को अपना बाजार हिस्सा गंवाने की संभावना होती है और परिणामस्वरूप नुकसान उठाना पड़ता है।

137. मैगोटॉक्स थाईलैंड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग 95000 मीट्रिक टन की उसकी संपूर्ण निर्यात बिक्री "स्पॉट सेल" के आधार पर है; इस प्रकार महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल छोड़कर। इसके अलावा, मैगोटॉक्स थाईलैंड ने कहा है कि वह पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में बिक्री शुरू कर देगा।

138. दी गई दलीलों, प्रदत्त सूचना, किए गए अनुरोधों और ऊपर यथा-अभिलिखित प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

क. विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्ववर्ती जांचों में परिभाषित किया गया है और वह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के समान वस्तु है।

ख. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ग. वर्तमान में कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से कोई आयात नहीं हुआ है।

घ. मौजूदा अवधि में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन और खपत में अन्य भारतीय उत्पादकों का महत्वपूर्ण हिस्सा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का भारतीय बाजार पर एकाधिकार नहीं है।

ड. प्रश्नावली के उत्तर के विश्लेषण से पता चलता है कि मागोटेक्स थाइलैंड द्वारा उसके अन्य सुदूर बाजारों से भारत में निर्यातों को पुनःनिर्देशित करने की पर्याम संभावना है और उनके सामने एकमात्र बाधा मौजूदा पाटनरोधी शुल्क है।

च. थाइलैंड से उत्पादकों का भारत में पाटन का इतिहास रहा है और उनके पास मुक्त रूप से निपटान योग्य उत्पादन क्षमता है, वे तीसरे देशों में पाटन कर रहे हैं, एफटीए के अन्तर्गत रियायतें प्राप्त करते हैं और काफी अधिक निर्यातोन्मुखी हैं।

छ. आवेदकों के संभावित और भावी निष्पादन के आकलन से पता चलता है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आने की संभावना है।

ज. मौजूदा शुल्कों को जारी रखना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

झ. अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव मामूली है।

ञ. चीन जन.गण. से पाटन और क्षति की संभावना सिद्ध करने के लिए कोई पर्याम साध्य नहीं है।

139. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी की राय है कि इस उपाय को थाइलैंड से आयातों के संबंध में आगे बढ़ाना आवश्यक है। भारत को थाइलैंड से कीमत प्रस्तावों तथा शेष विश्व को निर्यातों से पाटित और क्षतिकारी आयातों की मात्रा पर विचार किया गया है। तथापि, चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश नहीं की गई है।

140. वर्तमान लागू उपाय के समाप्त होने पर आसन्न पाटन और क्षति की संभावना की जांच करने के बाद, प्राधिकारी थाइलैंड के विरुद्ध भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-। खंड-। में प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 7/7/2017-डीजीएडी दिनांक 11 जून, 2018 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा यथा अनुशंसित और केन्द्र सरकार द्वारा पांच वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचना सं. 36/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 जुलाई, 2018 के माध्यम से यथा-अधिसूचित, लागू पाटनरोधी शुल्क को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में निर्दिष्ट राशि के अनुसार निश्चित प्रतिपाटन शुल्क को केंद्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार करने की स्थिति में इस अधिसूचना की तारीख से विस्तारित करने की सिफारिश की जाती है, जो संबंधित सामानों के सभी आयातों पर या थाईलैंड से निर्यात किया।

शुल्क तालिका

| क्र.सं. | शीर्षक / उप शीर्षक | माल का विवरण | मूलता देश | निर्यात के देश | उत्पादक | शुल्क राशि यूएस डॉलर प्रति एमटी में |
|---------|--------------------|---|-----------|----------------|--|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 7325 9100 | 'ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स' (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर) | थाईलैंड | थाईलैंड | मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड | 158.80 |
| 2 | -do- | -do- | थाईलैंड | थाईलैंड | क्र.सं. 1 में दर्शाए गए को छोड़कर कोई अन्य | 187 |
| 3 | -do- | -do- | कोई अन्य | थाईलैंड | कोई अन्य | 187 |
| 4 | -do- | -do- | थाईलैंड | कोई अन्य | कोई अन्य | 187 |

इ. आगे की प्रक्रिया

141. इस सिफारिश से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
DEPARTMENT OF COMMERCE
(Directorate General of Trade Remedies)
FINAL FINDING

New Delhi, 12th April 2023

(Case No. AD (SSR)-05/2022)

NOTIFICATION

Subject: Sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of 'Grinding Media Balls excluding Forged Grinding Media Ball' originating in or exported from China PR and Thailand.

F. No. 7/13/2022-DGTR- Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules') thereof –

The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application from AIA Engineering Ltd. and Welcast Steels Ltd. (hereinafter also referred to as the "applicants" or the "domestic industry") seeking initiation of a sunset review of the anti-dumping duty imposed on imports of 'Grinding Media Balls excluding Forged Grinding Media Ball' (hereinafter referred to as "GM Balls" or the 'subject goods' or the 'product under consideration' or the 'PUC' originating in or exported from China PR and Thailand (hereinafter referred to as the 'subject countries').

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority had initiated an original investigation concerning imports of “Grinding Media Balls excluding forged Grinding Media Balls” originating in or exported from Thailand and China PR vide Notification No. 14/34/2010-DGAD dated 23rd May 2011. The final findings notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/34/2010-DGAD dated 22nd May 2012, recommending the imposition of definitive Anti-Dumping Duty (ADD) on the imports of the subject goods. Definitive anti-dumping duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 36/2012- Customs (ADD) dated the 16th of July 2012.
2. The Authority had thereafter initiated the first sunset review investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries vide Notification No. 7/7/2017-DGAD dated 04th July 2017. The final findings notification was issued by the Authority vide Notification No. 7/7/2017-DGAD dated 11th June 2018 recommending the extension of the duties in force on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries. The anti-dumping duties were extended by the Ministry of Finance vide Notification No. 36/2018-Customs (ADD), dated 13th July 2018. The said duties were levied for a period of 5 years and are set to expire on 13th April 2023.
3. In terms of Section 9A (5) of the Act, ADD imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition; and the Authority is required to review, whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows:

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”

4. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence submitted by the applicants, the Authority issued a public notice vide notification no. 7/13/2022-DGTR dated 30th September 2022, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules to review the need for continued imposition of ADD in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of the said ADD is likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
6. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject countries in India about receipt of the application for sunset review investigation before proceeding to initiate the present investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 30th September 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating sunset review investigation concerning anti-dumping duty imposed on imports of the subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 30th September 2022 to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the applicants. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.

d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

e. The Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- i. Magotteaux Co Ltd., Thailand ("Magotteaux Thailand")
- ii. Magotteaux Alloyed Material (Suzhou) Co Ltd., China ("Magotteaux China")

f. In response to the above notification, the following producers/exporters have responded and submitted/filed exporters' questionnaire responses:

- i. Magotteaux Co Ltd., Thailand.

g. The Authority forwarded a copy of the notification and questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

- i. ACC Ltd.
- ii. Alcon Cement Company Pvt. Ltd.
- iii. Ambuja Cement Ltd.
- iv. Andhra Cement Co. Ltd.
- v. Anjani Portland Cement Ltd.
- vi. Asian Concretes and Cements Pvt. Ltd.
- vii. Bharat Heavy Electricals Ltd.
- viii. Binani Cement Ltd.
- ix. Birla Corporation Ltd.
- x. Cement Manufacturing Co. Ltd.
- xi. Century Cement, Century Textiles & Industries Ltd.
- xii. Chariot Steel & Power (P) Ltd.
- xiii. Chowgule & Company Ltd.
- xiv. Chunar Churk Cement Ltd.
- xv. Deccan Cements Ltd.
- xvi. Diamond Cements Ltd.
- xvii. Durga Cement, Andhra Cements Ltd.
- xviii. ECO Cement India Ltd.
- xix. Grasim Industries Ltd.
- xx. Green Valley Industries Pvt. Ltd.
- xxi. Gujarat Sidhee Cement Ltd.
- xxii. Gujarat State Electricity Corporation Ltd.
- xxiii. Heidelberg Cement India Ltd.
- xxiv. Hindustan Zinc. Ltd.
- xxv. India Resources Ltd.
- xxvi. J.K Cement Ltd.
- xxvii. J.K Lakshmi Cement Ltd.
- xxviii. Jaiprakash Associates Ltd.
- xxix. Jaypee Infrastructure Ltd.
- xxx. Jindal Steel & Power Ltd.
- xxxi. Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd.
- xxxii. Keerthi Industries Ltd.
- xxxiii. Kesoram Industries Ltd.
- xxxiv. Khyber Industries (P) Ltd.
- xxxv. Lafarge India Pvt. Ltd.
- xxxvi. Madras Cements Ltd.
- xxxvii. Maharashtra State Power Generation Company Ltd.
- xxxviii. Mahi Cement (Banswara) Ltd.
- xxxix. Birla Corporation Ltd.
- xl. Mandovi Pellets Ltd.
- xli. Megha Technical & Engineers Pvt. Ltd.
- xlii. Meghalaya Cements Ltd.
- xliii. MSP Steel and Power Ltd.
- xliv. Murali Industries Ltd.

- xlv. My Home Cement Industries Ltd.
- xlvi. NCL Industries Ltd.
- xlvii. NGS White Cement Company Ltd.
- xlviii. OCL India Ltd.
- xlix. Orent Cement Ltd.
 - I. Panipat Thermal Power Station
 - li. Panyam Cements & Mineral Industries Ltd.
 - lii. Parsakti Cement Industries Ltd.
 - liii. Penna Cement Industries Ltd.
 - liv. Prism Cement Ltd.
 - lv. Rain Commodities Ltd.
 - lvi. Rashmi Cement Ltd.
 - Ivii. Reliance Infrastructure Ltd.
 - Iviii. Sagar Cements Ltd.
 - lix. Saloni Industries
 - lx. Samruddhi Cement Ltd.
 - lxi. Sarda Energy & Minerals Ltd.
 - lxii. Saurashtra Cement Ltd.
 - lxiii. Shiva Cement Ltd.
 - lxiv. Shree Cement Ltd.
 - lxv. Shree Digvijay Cement Company
 - lxvi. DCM Shriram Ltd.
 - lxvii. Suday Minerals & Chemicals (P) Ltd.
 - lxviii. Tata Chemicals Ltd.
 - lxix. The India Cements Ltd.
 - lxx. Trinayani Cement (P) Ltd.
 - lxxi. Trumboo Industries Private Ltd.
 - lxxii. U.P Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
 - lxxiii. Ultratech Cement Ltd.
 - lxxiv. Vasavadatta Cement
 - lxxv. Zuari Cement Ltd.

- h. In response to the above communication, none of the importers or users responded or submitted importer/user questionnaire responses/legal submissions and/or registered as interested parties.
- i. The Authority sent questionnaires to the following known user association of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. National Council for Cement and Building Materials
 - ii. Cement Manufacturers Association
 - iii. The Indian Mining and Engineering Journal
- j. In response to the above notification, none of the user associations responded or submitted any submissions and/or registered as interested parties.
- k. The Authority, upon request made by the interested party, granted extension of time to file the questionnaire responses, vide communication dated 10th November 2022. The Authority, upon request made by the responding exporter, granted further extension of time to file the additional information, vide communication dated 03rd February 2023. The Authority during the course of investigation sought additional information from all the interested parties.
- l. Since it was not possible to maintain physical public file due to ongoing COVID-19 pandemic, all the interested parties were requested to e-mail non-confidential versions of their submissions/responses/comments filed by them to all the other interested parties.
- m. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2021 to 31st March 2022. (12 months). The injury examination period has been considered as the period from 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the POI.

- n. The transaction-wise imports data for the period of investigation and the preceding three years was procured from the DG Systems. The Authority has relied upon data of DG Systems for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India and for comparison and reconciliation with the responses filed by the exporters.
- o. Further information was sought from the applicants and responding exporters/ importers to the extent deemed necessary.
- p. The non-injurious price (hereinafter referred to as “NIP”) has been determined, based on the optimum cost of production and reasonable profits, for the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been worked out so as to ascertain whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of injury to the domestic industry.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 16th February 2023. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- r. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in this final finding notification.
- s. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding notification, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- t. Physical verification of the information provided by the domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this final finding notification.
- u. Due to the worldwide outbreak of COVID-19 and consequent restrictions on physical movement imposed by the different countries, including India, the physical inspection through on-the-spot verification of the information submitted by the exporters were not carried out by the Authority. The desk verification of the information provided by the producers/ exporters, was not conducted as the responding producer/exporter did not submit documentary evidences in support of their submissions.
- v. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- w. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 05th April 2023, and the interested parties were allowed time up to 10th April 2023 to comment on the same. The comments on disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.
- x. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this final finding notification on the basis of the facts available.
- y. ‘****’ in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- z. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$1= 75.37.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions by the other interested party

8. The submissions made by interested party with regard to the product under consideration and like article are as follows:

- No PCN methodology was notified by the Authority in the previous investigations and the same shall be continued in the present case.

C.2. Submissions by the domestic industry

9. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:

- The product under consideration is the same as been defined in the previous investigations. The subject good is a like article to the product produced by the domestic industry as established in the previous investigations.
- The domestic industry stressed on the need for PCN methodology as there has been huge difference in the price of the product sold by the domestic industry and Magotteaux.

C.3. Examination by the Authority

10. The product under consideration as defined in the original investigation is reproduced hereunder: -

“8. The product under consideration is ‘Grinding Media Balls’ (excluding Forged Grinding Media Balls). ‘Grinding Media Balls’ (in short, ‘GM Balls’) are produced in different sizes, shapes and compositions for use in diverse applications. Further, it is available different hardness depending upon varying requirements of the customers.

9. The product under consideration is extensively used in cement build materials, metal mining, coal slurry, thermal power plant, chemical engineering, ceramic industry, dope industry, light industry such as papermaking and magnetic material etc for powder preparation. The subject goods are classified under Customs sub-heading 7325 9100 of Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.”

11. The present investigation is a sunset review investigation. There are no submission by any interested party requesting review of the scope of the product under consideration. The scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

12. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject countries in terms of product characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process & technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the Rules.

13. The Authority has noted the domestic industry’s submissions on the need for PCN methodology. However, the information on record shows that there are no imports from the subject countries. Further, the responding exporter’s questionnaire response shows no exports to India. It is also noted that no PCN methodology was notified by the Authority in the original investigation and in the first sunset review investigation. Therefore, the Authority has not defined PCNs for the present investigation. However, wherever required grade to grade comparison has been undertaken for fair comparison.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions by other interested party

14. The following submissions have been made by the other interested party:

- The review petition is deficient as no authorization letter/ requisite certificate in Format X has been enclosed for Welcast Steels Ltd. No evidence of support has been enclosed for Welcast Steels Ltd.
- Other domestic manufacturers have not participated/supported the petition. The domestic industry is aiming to monopolise and coerce them to shut down their operations.

D.2. Submissions by the domestic industry

15. The following submissions have been made by the domestic industry:

- AIA Engineering Ltd. and Welcast Steels Ltd. account for a major proportion of the Indian production of the like article.
- Apart from the domestic industry, there are 11 other domestic producers who predominantly cater to the domestic demand. Support letters received from four domestic producers have been adduced as legal submissions before the Authority.
- Non-participation by other domestic producers is owing to the fact that they're (i) MSME (ii) cater only to domestic demand (iii) have no exports.
- As regards the contention that the review petition is deficient, it is submitted that the applicants have complied with the requirements of the petition and the same was duly scrutinised by the Authority.
- As regards no other domestic manufacturers have participated, the domestic industry has submitted support letters from other domestic manufacturers seeking continued imposition of duties.

D.3. Examination by the Authority

16. Rule 2 (b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

17. The application has been filed by AIA Engineering Ltd. and Welcast Steels Ltd. There are 11 other producers of the product under consideration in India. During the course of the investigation, four producers have filed support letters supporting the application and the requested for extension of anti-dumping duty.

18. The Authority notes, on the basis of information on record, that the applicants account for ***% of Indian production and accounts for a major proportion of the total Indian production. Further, the applicants have not imported the subject goods during the period of investigation; and are not related to any exporter or producer of the subject goods in the respective subject countries or any importer or user of the product in India within the meaning of Rule 2(b).

19. Therefore, having regard to information on record, the Authority, concludes that the applicants constitute ‘domestic industry’ within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. Even though the standing requirements are not applicable to review investigations, the Authority concludes that the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by other interested party

20. The following submissions have been made by the other interested party:

- The applicants have claimed excessive confidentiality in their application. Reliance is placed on *Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority and Ors*, [2006 (202) ELT 23 (SC)]

E.2. Submissions by the domestic industry

21. The following submissions have been made by the domestic industry:

- Not only has the respondent claimed excessive confidentiality in contravention to the Trade Notice, Rules, and principles of natural justice, but also their explanations to the same is absurd and illogical. Reliance is placed on CESTAT order in the matter of *H.R. Johnson v. Designated Authority* [2005(185) ELT 125 (Del)] and other findings of the DGTR wherein the responses were rejected owing to failure to furnish meaningful non-confidential version of the information claimed confidential.
- As regards the contention that the petition is excessively confidential, it is submitted that the argument is severely belated and should therefore not be accepted. Further, Magotteaux has already been called upon by the Authority on its non-compliance to the Trade Notice, whereas the applicants have not been.

E.3. Examination by the Authority

22. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-Rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

23. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority had instructed Magotteaux to file revised response after adhering to the Trade Notice 10/2018. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.

24. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicants and the opposing interested parties. The Authority has noted that the questionnaire response initially submitted by the respondent was grossly insufficient and excessively confidential. Thereafter, the respondent was directed to provide complete EQR and sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority has noted that the response re-filed continues to be excessively confidential. In accordance with Rule 7(3), the Authority has disregarded that information that is not accompanied with a sufficient non-confidential version for the purpose of the final finding notification. The Authority made available to all interested parties the non-confidential version of evidence submitted by various interested parties. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**F.1. Submissions by other interested party**

25. The following submissions have been made by the other interested party:

- a. Prolonged duty of imposition is against the spirit of cooperation amongst ASEAN partners.
- b. If the duty is continued, the domestic industry will enjoy duty protection for an uninterrupted period of 10 years.

F.2. Submissions by the domestic industry

26. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. Magotteaux's manufacturing facilities in various countries has created trade barriers, eliminated competition through various trade actions, and maintained privileged trade access solely for their products.
- b. Despite the legal requirement and direction, Magotteaux India, a related entity of Magotteaux Thailand has failed to participate in the current investigation. This is in spite of it being an importer, selling and marketing office, for Magotteaux and having undertaken domestic sales during the period of injury.
- c. The questionnaire response submitted by the respondent is grossly inadequate and lacks sufficient response. The failure to provide a meaningful summary, meet the requirement sought by the Authority has impaired the domestic industry's right to defend its interest.

- d. There are no known imports of the product during the injury period. There is only negligible volume recorded under the HS code, of which the price is excessively disproportionate to the volume. The domestic industry requests the Authority to investigate the volume so reported.
- e. Even in the event of low volumes of imports, ADD can be continued. Reliance is placed on cases from various jurisdictions including India, Canada and EU.

F.3. Examination by the Authority

27. The Authority has considered the submissions made by the parties and concludes as follows:

- a. The Authority notes that the law clearly envisages that the anti-dumping duty is required to be extended from time to time if it is found that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty. Anti-dumping law is for removing unfair trade practice and providing a level playing field to the domestic industry. The Authority recommends anti-dumping duty only after following the requirements prescribed under the laws.
- b. It is noted that Magotteaux India Pvt. Ltd. participated in the hearing. However, despite multiple directions and requirement, the company has not cooperated with the Authority and has not provided relevant information in the current investigation. In contravention to the Trade Notice 11/2018, Magotteaux India has not registered itself as an interested party to the current investigation. Despite this Magotteaux India's representative participated in the oral hearing and spoke in support of Magotteaux Thailand. Even though the Authority directed Magotteaux Thailand to provide relevant information in respect of Magotteaux India, the Authority notes that desired information was not provided for Magotteaux India. The Authority considers that response from Magotteaux India was relevant and necessary in the present investigation, since Magotteaux Thailand stated that it intends to export the product to India in the event of cessation of ADD, Magotteaux India is selling the goods in the domestic market during the present period. Additionally, as seen from the EQR of Magotteaux Thailand, Magotteaux India is currently engaged in production whereas it was only a marketing arm as observed in the original investigation.
- c. As regards adequacy of information filed by Magotteaux Thailand, the Authority had issued deficiency questionnaire to Magotteaux Thailand thereby giving them opportunity to complete the response. However, despite giving multiple opportunities, Magotteaux Thailand has not provided the following information desired by the Authority:
 - i. Audited Financial Statements for the 2021-22, 2019-20.
 - ii. Profitability Statements for the last three years.
 - iii. Performance parameters in trend.
 - iv. Variation in cost and sales data.
- d. Magotteaux Thailand has not provided any documents in support of the information furnished in their questionnaire responses with regards to their Capacity, Cost of production and sales. However, an e-mail was received from the counsel of Magotteaux Thailand on 5th of April, 2023 at around 01:40 A.M. when the Authority was in the process of issuing the disclosure statement. The authority notes that the exporter was given several opportunities to provide relevant information to the Authority throughout the course of the present investigation. The exporter however has not provided the relevant information during the time limit. The documents filed by the exporter at the stage of the issuance of disclosure statement by the Authority is significantly belated and time barred. The Authority therefore does not accept the submissions made by the said exporter at such a belated stage for the purpose of the final finding notification. In view of the above, the Authority established facts based on the best facts available to it.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by other interested party

28. No submissions have been made by the other interested party with regard to the normal value, export price and determination of dumping margin.

G.2. Submissions by the domestic industry

29. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. China needs to be treated as a non-market economy for the reason that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces. Hence, the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
- b. Under Para 7, normal value for non-market economy country is required to be determined on the basis of prices of the subject goods in the market economy third country or price from such third country to the other countries, including India, or on some other reasonable basis. The applicants have suggested Thailand as an appropriate market economy third country for the present investigation
- c. The normal value for Thailand should be calculated on the basis of cost of goods sold by Magotteaux Co., Ltd., Thailand, the sole producer of the subject good in the country and reasonable profit margin.

G.3. Examination by the Authority

30. According to Section 9A(1)(c) of the Act, 'Normal value' in relation to an article means:

*(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Normal Value in China

31. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of

subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

32. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to this questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of Para 7 of Annexure I of the Rules.

33. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries have been determined as below.

34. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

35. None of the exporter/ producers in China have cooperated in the investigation. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proposes to proceed with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

All producers/exporters from China PR

36. In absence of sufficient information on record regarding the other methods as are enshrined in para 7 of Annexure I of the AD Rules, the Authority has determined the normal value by adopting the method "any other reasonable basis".

37. The Authority has therefore constructed the normal value for China PR, for the purpose of present investigation.

Normal value determination for M/s Magotteaux Co Ltd., Exporter/producer from Thailand

38. While examination of the respondent's questionnaire response, the Authority notes that there are significant variations in the data in the questionnaire response submitted. It is seen that;

- While Appendix 1 shows volume of exports to third countries is as *** MT, in the submission made on transaction wise sales data to third countries for product under consideration in period of investigation, the respondent reported exports of *** MT. It is unclear whether these transaction wise sales contain NPUC sales.
- The financial statement of the company, despite being required to submit for the last 3 years, the respondent has only submitted one. In Annexure 8, containing the financial statement for 2020-2021, which covers 9 months of period of investigation, it is seen that the company made a loss of *** million bhat in 2021 and a loss of *** million bhat in 2020, while in Appendix 7, company reported profit of *** million bhat for the company as a whole, *** million bhat profit in PUC and *** million profit in NPUC. No reconciliation has been provided in the response to show how a loss of *** million in 2021, turned into profit of *** million bhat in the period of investigation.
- In the third country transaction wise data reported in Annexure 1, of Part II EQR, Inland freight reported shows abnormal per unit cost, from as low as *** bhat per MT to as high as *** bhat per MT. The difference is significant considering it is charged for freight from factory to seaport. Similarly, ocean freight in respect of exports to Australia varies from as low as *** bhat per MT to as high as *** bhat per

MT, and Turkey varies from as low as *** bhat per MT to as high as *** bhat per MT. This significant variation is seen even on transactions for the same country during the same date such as Turkey – 30 August – freight *** bhat per MT and *** bhat per MT and, for Australia – 8 April – ocean freight reported varies from *** bhat per MT to *** bhat per MT.

39. Additionally, despite the Authority's direction to submit documentary evidence in support of their submissions and having provided a timeline of 10 days for the same, the respondent did not provide documentary evidence for desk-verification. In view of the above, Authority has determined the normal value based on the facts available in accordance to Rule 6(8).

Normal value of all other exporter/producers from Thailand

40. It is noted that M/s Magotteaux Co Ltd., Exporter/producer is the sole producer / exporter of the subject goods from Thailand. The normal value and export price from Thailand has been determined as per facts available.

Determination of export price of China PR and Thailand

41. None of the exporters from China PR have provided any information giving details of export price. The DG Systems data shows no imports of the product under consideration from China PR.

42. As regards Thailand, M/s Magotteaux Co Ltd., Thailand has responded to the investigation and stated that they have not exported the product under consideration to India. The Authority has verified the same through DG Systems data.

43. The Authority notes that there are no known imports of the product concerned from the subject countries during the POI. Therefore, actual dumping margin in respect of POI exports cannot be determined in the absence of the actual imports into India during the POI.

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions by other interested party

44. The following submissions have been made by the other interested party:

- a. The domestic industry is significantly export oriented and cannot allege recurrence of injury in case of cessation of duties.
- b. The Authority should investigate the need for inordinately prolonged period of protection and inherent inefficiencies of the domestic industry which attributes to their injury. Reliance is placed on SSR concerning imports of Caustic Soda from Saudi Arabia and USA, (1 August 2018), Phenol from Japan and Thailand, (1 July 2016) Plain Gypsum Plaster Boards from China PR, Indonesia, Thailand, and UAE (19 April 2018).
- c. The deterioration in the financial health of the domestic industry when the duties were in force are not the fault of Magotteaux.
- d. Calculation of non-injurious price should take into account the COVID-19, and capacity expansion that has resulted in increased cost of interest and depreciation.
- e. There is no merit in calculation of injury based on unmaterialised offers that are different and dissimilar from the domestic industry having no details of grade or PCN.
- f. There is no volume injury, price injury, or any adverse effect on profitability, cost of sales, installed capacity etc.
- g. Welcast working under protected environment of the duties have still suffered losses.
- h. There is no merit in claiming that duties imposed on the domestic industry in other jurisdictions are causing injury to the domestic industry. Infact, the domestic industry has not even challenged any of these duties. Their claim is baseless.
- i. Duties imposed on the domestic industry in other jurisdictions indicates that they are exploiting the Indian domestic users by overcharging for the PUC.

H.2. Submissions by the domestic industry

45. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. The domestic industry has not claimed continued dumping or injury. The existence of duty has in fact resulted in reasonable improvement in various economic parameters of the domestic industry.
- b. Even though there are no or negligible imports from the subject countries, there exists sufficient freely disposable capacity with the foreign exporters. Reference is placed on investigations conducted in various jurisdictions.
- c. Absence of current dumping or injury is not sufficient to conclude that the duty should not be continued.
- d. As regards the contention that the domestic industry is export oriented, it is submitted that they are domestic producers and not export oriented unit. Further as one of the leading producers of the subject goods in the global market, the domestic industry is engaged in exports.
- e. As regards the contention that the domestic industry's available capacity and expansions show no threat of dumping, it is submitted that the expansions have no correlation to threat of dumping faced from the subject countries.

| Particulars | UOM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | POI |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Sales of Domestic Industry | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 81 | 103 | 114 |
| Sales of Other Domestic Producers | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Subject countries as a whole | MT | 246 | 135 | 63 | 0 |
| Other Countries | MT | 83 | 120 | 9 | 52 |
| Demand/consumption | MT | 96,905 | 89,800 | 97,889 | 1,01,841 |

The sales of other domestic producers have been taken as their installed capacity from the market information submitted by DI.

- f. As regards the contention that the prolonged protection is against the spirit of ASEAN and that it is the inefficiencies of the industry that has attributed to the injury, it is submitted that no injury has been claimed by the applicants. Further, there is no bar on the period for which duties can be extended. Reference is placed on various investigations in India, EU, Brazil, Canada, USA where duties have been extended for 15-30 years.
- g. As regards the contention on deterioration in financial health is not related to Magotteaux, there is no volume injury, price injury or adverse effect on performance parameters, the applicants submit that they have not claimed continued injury or that Magotteaux has caused them injury.
- h. As regards the contention that calculation of NIP should take into account COVID-19 and other effect, the calculation of NIP shall be governed by the rules and practises laid down.
- i. As regards the contention, that there is no merit in calculation of injury based on unmaterialised offers having no details of grade or PCN, it is requested that the Authority evaluate the offers submitted which has details of grades.
- j. As regards the argument that Welcast despite being protected by the duty continues to suffer losses, it is submitted that these losses are not due to dumping. The domestic industry is in the process of phasing out production of subject goods at Welcast and hence the resultant reduced capacity utilisation.

H.3. Examination by the Authority

46. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.
47. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central

Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

48. The Authority notes that this being a sunset review of antidumping duty already in force, continuation of material injury to the domestic industry, as well as likelihood of continuation or recurrence of material injury needs to be examined in the context of actual or likely imports of the subject goods from the subject countries.

49. The Authority has examined the submissions made by the interested parties regarding the likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in case of expiry of duty. It is noted that the present investigation has been initiated in terms of Section 9A(5) of Customs Tariff Act which requires the Authority to determine whether the duty is required to be continued for a further period of five years and to examine the degree and extent of likely dumping and injury and the need for continuation or revocation of duty based on the information provided and submissions made by various interested parties during the course of the investigation. For the purpose of assessing current injury or continuation of injury during the injury period, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports on the domestic industry.

50. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has first examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.

51. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters, and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

52. In the instant case, the Authority notes that there are no known imports of the product under consideration in India. Therefore, in any case, the domestic industry could not have suffered continued injury due to dumped imports. Nevertheless, the Authority examined the performance of the domestic industry over the present injury period.

53. As regards the argument that Welcast despite being protected by the duty continues to suffer losses, the Authority notes that these losses are not due to dumping. The domestic industry contends that it is in the process of phasing out production of subject goods at Welcast and hence the resultant reduced capacity utilisation.

H.3.1 Volume effect of dumped imports on domestic industry

(i) Assessment of demand/apparent consumption

54. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and all other Indian producers, imports from the subject countries as per DG Systems data, and import from all other countries.

55. It is seen that the demand for the subject goods has increased during the period of investigation as compared to the base year and previous year.

(ii) Import volumes from the subject countries

56. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on volume of imports from the subject countries as per the DG System data. The factual position is as follows:

| Particulars | UOM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | POI |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Subject countries as a whole | MT | 246 | 135 | 63 | 0 |
| Other Countries | MT | 83 | 120 | 9 | 52 |
| Subject country imports in relation to | | | | | |
| Consumption | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| Trend | Indexed | 100 | 59 | 25 | 0 |
| Indian production | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| Trend | Indexed | 100 | 57 | 28 | 0 |
| Total imports | % | 75 | 53 | 88 | 0 |

57. It is seen that imports from subject countries have declined in both absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. Further, there were no imports of the product from subject countries in the present POI.

H.3.2 Price effect of the dumped imports

(i) Price undercutting

58. Since there are no known imports of the product under consideration from the subject countries, it is concluded that the subject imports have not undercut the prices of the domestic industry in the market.

(ii) Price suppression and depression

59. In order to determine whether the domestic industry is suffering suppressing or depressing effect on the prices, the Authority has considered the trends in costs and prices of the domestic industry. However, since there are no known imports of the product under consideration from the subject countries, it is proposed to conclude that the subject imports have not had any suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry in the market. The table below shows factual position with regard to the trends in the costs and prices of the domestic industry in the market:

| Particulars | UOM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | POI |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Cost of sales | Rs. /MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 102 | 99 | 133 |
| Selling price | Rs. /MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 96 | 88 | 113 |

60. It is seen that the increase in cost of production is not commensurately reflected in the increase of selling price of the domestic industry. However, the domestic industry has submitted that the foreign producers are likely to dump the product at injured price in the domestic market in the event of cessation of duties, and if so, the circumstances will result in price depression in the market, leading to material injury to the domestic industry.

H.3.3 Economic parameters of the domestic industry

61. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

(i) Production, capacity, capacity utilization and sales

62. The capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| Particulars | UOM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | POI |
|----------------------|-----------|---------|---------|---------|------|
| Capacity | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 117 | 117 | 117 |
| Production | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 96 | 91 | 97 |
| Capacity utilization | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| Trend | %/Indexed | 100 | 81 | 77 | 83 |
| Domestic sales | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 81 | 103 | 114 |
| Export sales | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 97 | 91 | 94 |

63. It is seen that the domestic industry has increased its installed capacity in 2019-20. The production and capacity utilization declined till 2020-21 and has increased in the POI. Domestic sales volumes declined till 2019-20 and has increased thereafter till the POI.

(ii) Market share in demand

64. Market share of the domestic industry, other Indian producers, imports from the subject countries and other countries are shown in the table below:

| Particulars | UOM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | POI |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Imports from all sources | % | 0.34% | 0.28% | 0.07% | 0.82% |
| Sale of domestic industry | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| Trend | Indexed | 100 | 88 | 102 | 108 |
| Sales of other domestic producers | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| Trend | Indexed | 100 | 108 | 99 | 95 |

65. It is seen that the share of the domestic industry decreased in 2019-20 but increased thereafter. The share of the subject imports has continued to remain nil (less than one percent) through the injury period.

(iii) Inventories

66. Inventory position with the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

| Particulars | UOM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | POI |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Average Inventory | MT | 5,413 | 7,551 | 7,853 | 7,630 |
| Trend | Indexed | 100 | 140 | 145 | 141 |

67. It is seen that average inventories with the domestic industry has increased in the period of investigation as compared to the base year and declined as compared to the previous year.

(iv) Profitability, cash profits and return on capital employed

68. Profit, profitability, cash profits, PBIT and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| Particulars | UOM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | POI |
|-------------------------|----------|---------|---------|---------|------|
| Profit/loss (PBT) | Rs./MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 74 | 48 | 41 |
| Total profit/loss (PBT) | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 60 | 50 | 46 |
| PBIT | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 60 | 50 | 46 |
| Cash profits | Rs. Lacs | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 63 | 56 | 56 |
| Return on Investment | % | ***% | ***% | ***% | ***% |
| Trend | Indexed | 100 | 62 | 60 | 40 |

69. It is seen that the profits, cash profits, PBIT and ROI of the domestic industry has declined continuously over the injury period.

(v) Employment, wages and productivity

| Particulars | UOM | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | POI |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Number of employees | Nos. | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 91 | 77 | 69 |
| Productivity per employee | MT | *** | *** | *** | *** |
| Trend | Indexed | 100 | 105 | 119 | 141 |

70. It is seen that the employment with the domestic industry has declined over the injury period. However, productivity of the domestic industry has increased significantly over the injury period and particularly in the POI as compared to the previous year as well as base year. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

(vi) Growth

71. While overall growth of the domestic industry over the injury period was negative both with respect to volume and price parameters, while the growth in volume parameters became positive in POI, the growth in price parameters remained negative.

(vii) Ability to raise capital investment

72. The domestic industry has not claimed material injury during the POI.

(viii) Magnitude of injury margin

73. The Authority has determined the non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials of the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed. The NIP so determined has been considered for calculating injury margin.

74. Since there are no imports of the subject goods from subject countries, the injury margin based on the exports during period of investigation has not been calculated. However, the Authority has relied upon calculated NIP for likelihood examination.

I. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

75. The Authority examined any known factors other than the subject imports which could be causing injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practises and competition between the foreign and domestic producers, developments in the technology and the export performance and productivity of the domestic industry. The Authority examines whether the factors other than dumped imports could be of injury to the domestic industry.

a) Volume and prices of imports from third countries.

76. It is seen that there are insignificant imports from other countries. Thus, volume and price of imports from third countries could not have been causing injury to the domestic industry.

b) Contraction in demand

77. It is seen that the demand for the product under consideration have increased in the POI as compared to the base year as well as the previous year.

c) Changes in pattern of consumption

78. No evidence has been brought by any interested parties about any material change(s) in the pattern of consumption in respect of the product under consideration.

d) Conditions of competition and trade restrictive practises

79. The Authority notes that the investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practises.

e) Developments in technology

80. No evidence has been brought by any interested parties about any developments/ changes in the existing technology.

f) Export performance of the domestic industry

81. The Authority notes that the injury information examined relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, it cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

g) Performance of other products

82. The domestic industry has provided the injury data for the product under consideration and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the applicants have not been considered.

83. In any case, the Authority holds that the applicants have not suffered any injury due to the subject imports.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION/ RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**J.1. Submissions by other interested party**

84. The following submissions have been made by the other interested party:

- a. Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 emphasises on the need to assess factors such as rate of dumping, capacity available, price effect and inventories. Reference is also placed on *Jindal Saw Ltd. vs Designated Authority* [2021 (376) ELT 107 (Tri-Del)], *Hubei Tri-Ring Forging Co. Ltd. vs Designated Authority* [2016 (342) ELT 473 (Tri-Del)] and *Nirma Ltd. vs Union of India* [2017 (358) ELT 146 (Guj.)].
- b. No presumption can be made on likelihood of substantially increased importation as there are no subject imports.
- c. Magotteaux' s plant is not solely dedicated towards India and caters to multiple markets developed over the 10 years of imposition of anti-dumping duty.
- d. The capacity available with domestic industry and further expansions undertaken by them shows that there is no threat of dumping.
- e. No information is available with the exporters regarding participation or offers made by the domestic industry.
- f. The exporter has made substantial increase to third country markets since the original investigation and SSR.
- g. It is known from Magotteaux India that the products sold by the company are contract manufactured by an independent third party locally in India.
- h. As regards the presence of the country manager of Magotteaux India during the public hearing, reference is placed on Trade Notice No. 11/2018, wherein the Authority categorically allowed any party, whether or not registered as an interested party, to attend the public hearing and provide comments on the disclosure statement.
- i. Magotteaux India and Magotteaux Thailand are group entities, but do not control each other. No information regarding Magotteaux India is available with Magotteaux Thailand.
- j. Magotteaux India is not required to cooperate with the current investigation as (i) they are not an exporter in the subject country of the PUC, (ii) have not imported the PUC in the POI and (iii) not enrolled as an interested party in the present investigation. Reference is placed on *Alleima Materials Technology (Jiangsu) Co Ltd. v. Union of India* [order dated 06 September 2022 in W.P. (C) 12894/2022].
- k. The price offers submitted by domestic industry are doctored and fabricated.
- l. The company has an inventory of *** MT of standardized products (as on 31 March 2022) and non-standardized products are manufactured and supplied against orders.
- m. Since the original investigation markets where sales have increased to are Middle East (2219%), Europe (1541%), Australia (452%) and South America (214%).
- n. Since the previous investigation, the markets where sales have increased to are South America (7349%) and Australia (259%).
- o. Nature of the information sought from Magotteaux India has no relevance to the present investigation and are trade secrets of Magotteaux India.

J.2. Submissions by the domestic industry

85. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. The decline in imports in the current period is due to the anti-dumping duty in force. The dumping shall resume at significant volumes in the event the duty ceases.
- b. The producers from the subject countries have a history of dumping. India is the second largest cement producer in the world and holds fair advantage in the production and conversion costs in steel and alumina mining which makes India a lucrative market for the subject goods.
- c. There is freely disposable present and potential capacities with the foreign producers. The surplus capacity of China has been observed by the Australian Commission in a recently concluded SSR on the product under consideration.
- d. The producers in the subject countries are significantly export oriented and has been dumping significantly in third countries.
- e. As there are no imports of the subject good, Magotteaux India has been attempting to retain its customers by offering domestically manufactured products in the market without disclosing the origin of the same.
- f. Magotteaux India has been attempting to establish the brand in the Indian market by offering product at dumped and injurious prices.
- g. As can be seen from the offers, Magotteaux India has been offering the product to the customer at ex-warehouse Raipur, Chhattisgarh prices. The dumping and injury margin determined as per the offers provided are significant as seen below:

a. Previous Offers:

| Particulars | Quantity | Dumping margin | | Range | Injury Margin | | Range |
|--------------|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | | (MT) | (\$/MT) | | % | (\$/MT) | |
| Offer 1 | *** | *** | ***% | 100-110 | *** | ***% | 20-30 |
| Offer 2 | *** | *** | ***% | 60-70 | *** | ***% | 0-10 |
| Offer 3 | *** | *** | ***% | 180-190 | *** | ***% | 50-60 |
| Offer 4 | *** | *** | ***% | 80-90 | *** | ***% | 10-20 |
| Total | *** | *** | ***% | 80-90 | *** | ***% | 10-20 |

b. Current Offers:

| Particulars | Quantity | Dumping margin | | Range | Injury Margin | | Range |
|--------------|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | | (MT) | (\$/MT) | | % | (\$/MT) | |
| Offer 1 | *** | *** | ***% | 10-20 | *** | ***% | 10-20 |
| Offer 2 | *** | *** | ***% | 20-30 | *** | ***% | 20-30 |
| Offer 3 | *** | *** | ***% | 10-20 | *** | ***% | 10-20 |
| Offer 4 | *** | *** | ***% | 10-20 | *** | ***% | 20-30 |
| Total | *** | *** | ***% | 10-20 | *** | ***% | 20-30 |

- h. The Authority should examine the likely performance of the domestic industry should the domestic industry reduce its prices to the extent of price offered by Magotteaux. It may be seen that the domestic industry will suffer significant financial losses and negative return on investments, as can be seen from the table below:

| Particulars | UOM | Actual | As per Offer Price |
|---|---------|--------|--------------------|
| Net Sales Realisation per Unit | Rs. /MT | *** | *** |
| PBT (Profit before Tax) | Rs. /MT | *** | (***) |
| PBIT (Profit before Interest & Tax) | Rs. /MT | *** | (***) |
| Cash Profit (PBT+ Depreciation) | Rs. /MT | *** | (***) |
| PBIT as % of Average Capital Employed (ROI) | % | ***% | (***)% |

- i. Magotteaux has resorted to third country dumping which has resulted in significant price undercutting, loss of potential orders, and price injury in a number of countries.
- j. As stated in the EQR, the respondent has developed 72 markets as a result of the antidumping duty order on PUC from India. Further the company intends to export the product to India only in the event of removal of duties.
- k. The respondent has claimed no change in production capacity despite an intention to sell in the Indian market thereby leading to the conclusion that they've unutilised capacities, they intend to divert products from other markets to India and that the Indian market is highly price attractive.
- l. The assessment of likely and potential performance of the applicants show that the domestic industry would have done much better in the absence of dumping and is likely to deteriorate if the duties cease.
- m. As regards the respondent's contention that no likelihood can be determined as the volume of imports have remained low to 0, it is submitted that the dumping and injury has been offset by the duty in force. Further, lack of imports during the POI is not presumptive that the imports shall not flood the market once the duties cease.
- n. As regards the contention that Magotteaux's plant is not solely dedicated to catering to India, it is the respondent's own submission that they have developed over 72 markets to utilise the capacities when duties came into force. Logistically and economically, India is more lucrative to the respondent than the other 46 countries which are already being catered to by the other manufacturing units of Magotteaux which has proximity to these regions.

J.3. Examination by the Authority

86. As there is no known import of the product under consideration from any of the subject countries, the Authority has determined whether dumping is likely to recur in the event of cessation of ADD, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry. The applicants provided evidence of likelihood of recurrence of dumping in its petition and supplemented the same during the course of the investigation and submitted that the same is likely to cause injury to the domestic industry. The submissions made by the interested parties and evidence on record has been examined by the Authority. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to threat of material injury in terms of Annexure-II (vii) of the Rules and other relevant factors brought on record. The present investigation being a sunset review of anti-dumping duty currently imposed, and under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of the anti-dumping duties is warranted in the event of cessation of anti-dumping duty.

87. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia* for factors which are required to be taken into consideration, viz;

- i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
- ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
- iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and
- iv. Inventories of the article being investigated.

88. The Authority has, *inter alia*, considered the above requirements and following parameters in order to determine whether dumping is likely to recur in the event of cessation of ADD, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry. Further, the Authority considers that the above parameters are required to be applied having regard to the fact that there was an ADD in place. Therefore, the Authority has examined, considering the above parameters, whether there is a significant threat of material injury to the domestic industry in the event of cessation of ADD:

- a. **Dumping in respect of exports to third countries**

89. The domestic industry contended that the subject producers are exporting the product to a number of third countries and the same are at dumped prices. While there is no response from Chinese producers, the sole Thai producer has responded and provided relevant information. The Authority has examined exports from the subject countries to various countries globally and determined whether the same are at dumped and injurious prices.

Thereafter, the Authority has determined the volume of exports to various countries globally and determined the volume of exports at dumped and injurious prices. The Authority has also compared these exports with the selling price of the domestic industry in order to ascertain whether the exporters are likely to find Indian market attractive enough in terms of prices prevailing in the Indian market and the prices at which exporters are selling in third countries. Summarized position is as follows:

| Particulars | Absolute volume | | | In relation to Indian consumption | | |
|---|-----------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------|--------|
| | As per EQR | As per Trade Map data | | As per EQR | As per Trade Map data | |
| | Magotteaux | Thailand | China | Magotteaux | Thailand | China |
| | (In MT) | (In MT) | (In MT) | (In %) | (In %) | (In %) |
| Volume of exports to third countries below normal value | *** | *** | *** | 81.49% | 91.33% | 54.47% |
| Volume of third country exports below NIP | *** | *** | *** | 10.31% | 1.69% | 6.44% |
| Volume of third country exports below selling price prevailing in India | *** | *** | *** | 13.98% | 1.61% | 13.73% |

90. Following may be seen from the table above:

- *** MT of exports by the exporter is at dumped price which amounts to 81.49% of total Indian demand. The declared capacity of the exporter is *** MT. This indicates that almost 89% of exports are at dumped prices and the exporter is making exports at significant loss.
- *** MT of exports by the exporters is at injurious price. This injurious volume of exports accounts for 10.31% of total Indian demand.
- *** MT of exports are being made by the exporter at price below the price at which goods are being sold in the Indian market. The exporters will find the Indian market attractive to divert this volume of export to India, particularly when it is making losses. This price attractive volume of exports constitutes almost 14% of Indian demand.

91. It is thus seen that the exporter is highly export oriented and dumping goods all over the world. Significant volume of exports being made at dumped and injurious price. The exporter is incurring significant losses. The dumped, injurious and price attractive third country exports is significant in relation to Indian demand and sufficient to cause disruption in the domestic market. Thus, cessation of duty is likely to lead to significant volume of exports to India at dumped and injurious price which will consequently lead to injury to the domestic industry.

b. Price offers made in Indian market

92. The applicants have not provided evidence regarding price offers by the Chinese producers. The applicants have produced many price offers given by Magotteaux India. Some of the price offers show country of origin as Thailand. During the course of the investigation, the Directorate contacted 10 companies which had allegedly received offers from Magotteaux India. Out of the 10 companies, 5 companies have informed the Directorate that they have been approached by Magotteaux Group for sale of the subject goods. This indicates a clear intention by Magotteaux Group to sell the subject goods in India. It is reiterated that *** MT of exports by the exporter is at dumped price which amounts to 81.49% of total Indian demand. The declared capacity of the exporter is *** MT. This indicates that almost 89% of exports are at dumped prices and the exporter is making exports at significant loss *** MT of exports by the exporters is at injurious price. Further, this injurious volume of exports accounts for 10.31% of total Indian demand. It is therefore seen that there is a likelihood that in the event of cessation of ADD on the PUC, the responding exporter/producer shall start dumping in the Indian market causing injury to the domestic industry.

93. Further, the Authority wrote to Magotteaux Thailand and a number of consumers identified by the applicants to provide the details of these offers. Magotteaux Thailand was directed to provide details of lost orders in third country markets, inventory, markets developed subsequent to the previous SSR and price offers made by its related Indian entity, Magotteaux India. Magotteaux Thailand responded to certain questions and claimed to have no information available with them regarding the others. The same is being dealt in detail as follows;

94. As regards Magotteaux Thailand's claim that no information is available with them regarding price offers provided by the applicants, the Authority notes that Magotteaux India offers contain significant information clearly showing offers as "Magotteaux Group" with no indication therein that the price offer is based on a purchase of a product from Indian market or it is of Thailand origin. Both Magotteaux Thailand and Magotteaux India attended the public hearing and Magotteaux India representative made statement that there were several such offers in the market. The Authority also notes that the language of the offer given by Magotteaux India gives an impression of supply of Magotteaux product.

95. As regards Magotteaux Thailand's statement that it does not have any control over Magotteaux India and vice versa, the Authority notes that the Magotteaux Thailand had identified Magotteaux India as an "associated entity". Further, while the questionnaire requires information about Magotteaux India, the exporter stated that the requirement for the same does not arise in view of absence of imports during the POI. The exporter has however given three channels and identified supplies through Magotteaux India and direct purchase and sale by Magotteaux India as channel of sales. The Authority notes that there are admittedly no imports of the product during the present period and therefore the Authority is required to determine likelihood, where potential imports upon cessation of ADD are important and relevant. Given the relationship and channel of distribution, response from Magotteaux India was relevant and necessary. The Authority sought information about Magotteaux India in order to verify the claims of the domestic industry on its price offers and supply of the product. This was important in view of the fact that the offers given by Magotteaux India makes significant references about Magotteaux Group. Magotteaux India, inter-alia, stated "*Celebrated our 100 years of foundry activity Magotteaux has played a leading role in the development of Grinding Media and... With over 500,000 MT of world-wide capacity, Magotteaux has achieved and consolidated a successful track record to serve numerous different customers across the globe and provide wide range of alloys specifically adapted...'; 'Because we belong to a Worldwide Group present in every continent, we know the most effective way to supply in time, with the right forwarders, duly clearing the goods in time, performing the right inspections and optimizing international transport and freight costs'; 'With our well spread manufacturing network... sourcing origin may be adapted upon request and planning to meet your expectation. We ensure continuous supply regardless of geography and political instability.'*" The responding exporter claimed that both the group companies do not control each other and therefore the information regarding Magotteaux India could not be furnished. It is however noted that Magotteaux Thailand has identified Magotteaux India as an associated entity and has identified two channels out of three where Magotteaux India is involved. Further, the Director of Magotteaux India attended the public hearing and made statements, which were not limited to Magotteaux India and extended to Magotteaux Thailand. It is also seen that the offers by Magotteaux India makes significant references to the Group, and provides details of the Group, their 100 year of experience, worldwide manufacturing network etc. The Authority does not consider that Magotteaux Thailand can claim Magotteaux India as unaffiliated. Further, the manner in which offers have been given by Magotteaux India and the questionnaire response filed by Magotteaux Thailand (stating absence of exports due to ADD, willingness to supply after removal of ADD, participation in the hearing and statements orally made at the time of hearing, etc) cannot absolve Magotteaux Thailand from providing relevant information to the Authority. Since the objective of these questions was to ascertain likelihood of dumping in the event of cessation of ADD, the information was considered relevant and necessary. It has been a practice of the Authority to require a response from the related party involved in production or sale of the product under consideration. Magotteaux Thailand has not provided relevant information relating to Magotteaux India. The Authority is therefore constrained to establish facts based on information and document available on record or otherwise publicly available.

96. Indian consumers were directed to provide details of purchases/ price, details of manufacturer of the subject merchandise made from Magotteaux India, and the difference in the product offered by Magotteaux India and the domestic industry. Of the ten consumers approached by the Authority 5 consumers have stated that they have been approached by Magotteaux for sale of the PUC.

97. The Authority has perused the offers presented by the domestic industry on record. The Authority provided an opportunity to the responding exporter to rebut the allegation of the domestic industry and asked for details of sale, purchase and offers made by Magotteaux India but the information sought was not provided by the exporter. Some of the consumers approached by the Authority have confirmed that Magotteaux had approached them for sale of the PUC. Therefore, the Authority takes note of the submissions of the domestic industry that:

- i. Magotteaux India is a selling arm of Magotteaux Thailand in India. The domestic industry contended Magotteaux India has offered either Indian or Thai product with a view to establish its market so that it can export significant volumes once the ADD ceases. Magotteaux Thailand clarified that it has supplied a product made in India. In its questionnaire response, Magotteaux Thailand has also stated its intention to export the product in the event of cessation of ADD.
- ii. The price offers by Magotteaux India contain detailed information, including the product type, volume offered, price basis, etc.

iii. The domestic industry contended that these prices are an indicative price at which Magotteaux Thailand may export to India, in the event of cessation of anti-dumping duty.

b. Freely disposable production capacity

98. The domestic industry contended that the Chinese and Thai producers are holding significant freely disposal production capacity. The information provided by the exporter and the domestic industry was examined in detail. Following is observed:

- i. Whereas the domestic industry contended that the Thai producer holds a production capacity of 1,40,000 MT, the questionnaire response filed by Magotteaux Thailand shows a capacity of *** MT with them.
- ii. Whereas domestic industry reported total export volumes of 93,217 MT from Thailand during the POI, the questionnaire response filed shows export volume of *** MT by Magotteaux.
- iii. The Thai producer is having a capacity utilisation of ***% during the present POI.

99. The Authority also notes that in their submission, Magotteaux has stated that since the original investigation markets where sales have been increased are Middle East, Europe, Australia, and South America. Further, since the previous investigation, sales have increased to South America and Australia. The Authority notes that even though the exporter has stated that it has developed a large number of markets globally, it has also stated in their EQR that its entire sale in global market are on spot basis. Thus, these markets have been developed as spot markets, and the exporter has not committed any part of capacities for supplies to these markets. Therefore, barring domestic consumption (of below *** MT), entire capacity with the exporter is available for sale in any of the global markets, including India. It is seen that more than 90% of the capacity with the exporter is freely disposable for any market.

100. As regards China, the Authority notes that Chinese producers/exporters have not cooperated in the current investigation. The domestic industry has provided evidence of capacity and demand of China. However, the evidence pertains to the 8 years prior to the POI. The Authority considers the evidence is not recent and close to the period of investigation to establish that the Chinese producers have significant freely disposable production capacity with them.

101. The capacity, production, and demand of the subject goods in Thailand as submitted by the responding exporter are as under:

| Particulars | Unit | Thailand |
|--|------|----------|
| Capacity | MT | *** |
| Production - PUC | MT | *** |
| Production - NPUC | MT | *** |
| Unutilized capacity | MT | *** |
| Demand | MT | *** |
| Freely Disposable Capacity | MT | *** |
| Demand in India | MT | 1,01,841 |
| % of freely disposable capacity of Indian demand | % | 113% |
| % of surplus capacity of Indian demand | % | 18% |

102. However, Magotteaux Thailand has not provided any documents in support of the information furnished in their questionnaire responses with regards to their Capacity, Cost of production and Sales. The Authority established facts based on that information and have considered the best facts available to it.

103. The information on record thus shows that there are significant unutilized capacities in Thailand. Additionally, the producers in the subject countries are likely to divert their third country exports to India.

i. Attractiveness of the Indian market

104. The domestic industry has not provided any evidence to establish that the Indian market is attractive to the Chinese producers. The questionnaire response of Magotteaux Thailand shows that the company has developed close to 70 markets during the last 10 years. Further, Magotteaux group has production facilities in 5 countries. The Indian market is most lucrative to Magotteaux Thailand due to (1) increasing demand in India (b) proximity to Thailand as compared to other markets developed by the company (c) presence of selling arm in India, (d)

current business activities of Magotteaux India. Further, in its relevant part, Magotteaux Thailand has stated as followed in questionnaire response;

- a. The company intends to export PUC to India in near future, subject to removal of existing anti-dumping duties which have been in force for 10 years.
- b. The company does not expect any change in the production capacity, home market shipments, and exports to other markets (other than India). However, it is expected that the Company will receive a few orders from Indian customers and to that extent production may rise.
- c. The company does not have any long-term supply contract with any customer. All exports are on spot sales.

ii. Inventories

105. Magotteaux Thailand reported an inventory of standardized products (as on 31 March 2022) as *** MT. The Company further stated that non-standardized products are manufactured and supplied against orders, while standardized products can be supplied from inventories. The authority notes that both domestic industry and exporters have stated that a significant part of production is against specific orders. Under the circumstances, an inventory of *** MT of standardized products is quite significant, having regard to available demand for such a standardised product in India. While there is no information on record with regard to segregation of demand between standardised and non-standardised products, even on aggregated basis, inventory of *** MT constitutes about one-month consumption in India and is therefore quite significant.
106. It has been contended by the domestic industry that they would start suffering significant financial losses, cash loss and negative return on investment, should the domestic industry lose its domestic sales to the extent of the volume of likely import. Alternatively, if the domestic industry matches the third country export price of Magotteaux Thailand and prevent imports, the profitability of the domestic industry may again decline to a situation of financial losses, cash losses and negative return on investment. Thus, in both the situations, the domestic industry is likely to suffer financial losses, cash losses and negative return the investment should the present duties be allowed to cease.
107. No information is provided by the domestic industry on inventories held by the Chinese producers.

Conclusions on Likelihood

108. There are sufficient evidence enumerated above to establish that there is likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty against Thailand. As regards China, the Authority considers that the evidence provided by the domestic industry is not sufficient to establish likelihood.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

K.1. Submissions by other interested party

109. The following submissions have been made by the other interested party:
 - a. In light of the effect of COVID-19 in the period of injury, imposition of duty shall create a dominant position and monopolistic market making the cost of goods uneconomical and burdensome.
 - b. The submissions made by the domestic industry as to how the subject importers does not keep the consumers interest in mind is illegal and sans any basis in fact. The same should be ignored by the Authority.
 - c. Magotteaux India Pvt Ltd. is preferred by consumers in India. They get the PUC manufactured under contract from other non-supporting domestic manufacturers. This is not illegal, or in circumvention of the Rules.
 - d. Continuation of duties will lead to injury to the Indian consumers who are subject to the monopolistic attitude of the applicants.

K.2. Submissions by the domestic industry

110. The following submissions have been made by the domestic industry:
 - a. No response from the importers/ users have been received in the current investigation. Such non-participation indicates that the extension of anti-dumping duties will not have any adverse effect on the Indian industry.

- b. Support letters have been received from other domestic manufacturers seeking continued imposition of the duties so as to prevent recurrence of dumping and injury from the subject countries.
- c. The duration of the duty in force, the financial data of the domestic industry, the decline in price parameters over the injury period indicates that the domestic industry is not engaged in or is attempting to monopolise the market.
- d. The duty has been in force for the last 10 years with no adverse impact. The impact on consumers is negligible at 0.02%- 0.03%.
- e. The domestic industry has more than sufficient capacities to cater to the entire demand in the country and the subject imports are wholly unnecessary. There is no demand-supply gap for the subject goods in the Indian market
- f. The removal of duty will lead to surge in cheap imports which shall drive out the existing domestic industry and other domestic manufacturers of the subject goods.
- g. As regards the contention that Magotteaux India is preferred by the consumers, it is submitted that the related entity has failed to cooperate with the current investigation. Further, no evidence/ support has been provided to back this claim.
- h. Magotteaux has continued to ignore the consumer's interest in their attempt to re-establish themselves in the market.
- i. As regards the contention that contention on the effect of COVID-19 and that duty shall lead to monopoly, it is submitted that no relevance, factors, quantification, or existence has been provided by the respondent. Additionally, the existence of other domestic producers in the market ensure that the no dominant or monopolistic market is created.

K.3. Examination by the Authority

- 111. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with respect to the present investigation, including the possible effects of the anti-dumping duties on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, the interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, the effect of anti-dumping duties on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duties. None of the users or importers of the product under consideration has responded to the initiation notification or filed response to the questionnaire.
- 112. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties to this review investigation. Only the domestic industry has provided information sought in the Economic Interest Questionnaire. The applicants have supplied information related to the domestic industry as well as the user industry in its Economic Interest Questionnaire.
- 113. It is noted that the purpose of anti -dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the continuation of the anti-dumping duties might affect the price levels of the subject goods as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti -dumping measures would prevent the decline of the domestic industry that may ensue as a consequence of low-priced subject imports from the subject country and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the subject goods.
- 114. On the issue of monopolistic behaviour of the domestic industry, it is noted that the purpose of antidumping duty, in general, is to eliminate dumping which is causing or likely to (in case of SSR) cause injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in general interest of the country. From the antidumping rules, it is not borne out that a company, even if monopolistic, is prohibited from requesting to the Authority actions against the unfair imports. In the instant case, there are 11 producers of the product under consideration in India. In such situation, the question of monopolistic practice does not arise when these companies are competing with each other in the domestic market. The Authority notes that there were no known imports of the product in the POI from any source, and low volume of imports in the injury period. More than 99% of the demand for the product was met by Indian industry. Despite this, there was no substantiated case of monopolistic approach or action by the domestic

industry. Further, profits, cash profits, profit before interest and return on capital employed of the domestic industry has declined over the present injury period and have remained low over entire injury period. This would not have been the position, had the domestic industry been in a monopolistic situation or had the domestic industry adopted a monopolistic approach. It is evident that the profitability of the domestic industry has remained low despite absence of imports and predominantly entire share of Indian industry in the Indian market.

115. The domestic industry submitted that the user industry for the product is majorly mining and cement producers in the country. The domestic industry has provided information on the impact of anti-dumping duty on the eventual end consumer. The Authority has noted the submission of the domestic industry regarding impact of anti-dumping duty on the end consumers which is about 0.02%-0.03% as seen below. This is in a theoretical situation where the Indian industry increases the prices by the amount of ADD:

| Particulars | UOM | Cement | Mining |
|---|---------|---------|---------|
| Price of Finished Product | Rs. /MT | 7,000 | 70,000 |
| Production of Finished product | MT | 1050000 | 2000000 |
| Total Consumption of GM Ball | MT | 53 | 1,600 |
| Consumption of GM Ball per MT of Finished product | MT | 0.00005 | 0.00080 |
| Anti-Dumping Duty on GM Ball | INR/MT | 29,168 | 29,168 |
| Impact | INR/MT | 1.46 | 23.32 |
| % Impact | %/MT | 0.021% | 0.033% |

116. The Authority also notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to non-availability of the subject goods for the consumers. It is also noted that there is no demand - supply gap in the country and the domestic industry has sufficient capacity to cater to the entire Indian demand. The Authority notes that there were practically no imports of the product in the entire injury period and more than 99% of the demand for the product was met by Indian industry. None of the consumers participated and complained absence of material. On the contrary, some of the consumers stated that they were satisfied sourcing the material from domestic producers.

L. POST-DISCLOSURE COMMENTS

L.1. Submissions of the other interested parties

117. The submissions made by the other interested parties on the disclosure statement are as below:

- The Authority failed to address objection with respect to the absence of Welcast Steel Ltd's authorization in Format X.
- The Authority has not disclosed the four domestic producers who have supported the application.
- Rule 2(c) does not require a domestic related entity of the foreign producer to compulsorily participate in the investigation failing which adverse inference would be drawn against the foreign producer. Hence, not registering Magotteaux as an interested party is not in contravention to Trade Notice 11/2018.
- The confidentiality claims made by the exporter is the mirror image of claims made by the domestic industry. Therefore, the exporter cannot be accused of excessive confidentiality.
- There is a contradiction in the statement that the examination of injury is relating to the performance of the domestic industry in terms of domestic market and the observation that the domestic industry has suffered loss in the overseas market which affected their production and capacity utilization.
- The Authority should not have asked for the details of lost orders in third country markets.
- The offer price by Magotteaux India cannot be approximately in the range of landed value determined as the volumes sold by Magotteaux India are domestically manufactured and sold at minimal profit.
- The domestic industry is relying on fabricated invoices/offers which has to be verified and investigated.
- The volumes traded by Magotteaux India are minuscule in comparison to the volumes manufactured and sold by the domestic industry and the same cannot be considered for determining the dumping and injury margin.

- j. The Authority is relying on assumption and conjectures instead of undisputed facts which is Magotteaux India has not imported any PUC from the exporter.
- k. The demand for participation of Magotteaux India is fallacious as (i) despite being one of the distribution channels, Magotteaux India has not imported during the POI. (ii) Magotteaux Group consists of multiple entities, demanding Magotteaux India's participation would mean that all group companies of Magotteaux be forced to participate in the present investigation (iii) assurance provided by Magotteaux India to remove impact of duty is rhetoric as despite the same, the exporter could not find buyers. (iv) Magotteaux India is selling products manufactured by third party locally under contract which is not illegal and is irrelevant when determining possibility of likelihood or recurrence of dumping and injury.
- l. AIA Engineering Ltd has increased huge production capacity, which has resulted in the poor indices. The domestic industry is riddled with malafide and monopolistic behavior.
- m. The domestic industry is seeking perpetual anti-dumping duty which is against the purpose of anti-dumping duty as there are zero imports and after 10 long years, there is no justifiable reason to seek further protection.
- n. The domestic industry is exploiting Indian user by eliminating competition from Magotteaux.
- o. Magotteaux India is a group entity of Magotteaux of which Magotteaux Co. Ltd., Thailand is also one such entity. Merely because Magotteaux India belong to same Magotteaux group and therefore, Magotteaux India is required to participate, then all group companies of Magotteaux may also be forced to participate in the present investigation.

L.2. Submissions of the domestic industry

118. The submissions made by the domestic industry on the disclosure statement are as below:

- a. Magotteaux Thailand's submissions on the day of disclosure statement is belated. They have throughout the investigation blatantly disregarded the time limits prescribed by the Authority, Rules and Law.
- b. The Respondents has failed to provide prescribed information as per questionnaire, circulate meaningful non confidential version of the questionnaire, submit relevant documents for verification etc. Magotteaux Thailand failed to cooperate during the investigation.
- c. Non-confidential versions of the submissions made at the delayed stage on 05th April 2023, was not circulated to the domestic industry. The domestic industry is unaware of the contents in these submissions.
- d. The exporter's questionnaire instructs for information to be filed by all related entities. The lack of participation by Magotteaux India, the related entity, who is an importer, selling and marketing office of Magotteaux Thailand, has made domestic sales in the injury period and is offering customers the subject goods at dumped and injurious prices has significantly impeded the investigation.
- e. Magotteaux India's non-cooperation prevents the Authority from meaningfully analysing details of the purchase, operations, units involved and the channel of distribution in the current investigation.
- f. Magotteaux Thailand and India are controlled by Magotteaux Group, are affiliated and has common directors. Transaction details disclosed in the annual report includes sales, and purchase of goods and management consulting between these companies.
- g. The calculation of export price on the offers made by Magotteaux India is as per the practise of the Authority. This approach has been taken in investigations in various jurisdictions including Catalyst from Denmark, PIB from EU, Singapore, Thailand, Japan, Brazil and Korea RP and Seamless Tubes from Austria, Czech Republic, Russia, and Ukraine. Reference and reliance is placed on the Anti-dumping investigation concerning imports of Caustic Soda from Qatar dated 7th October 2002.
- h. Magotteaux Group intends to create global monopoly as is seen from the history of trade remedial measures; selling dumped products in third country market, loss suffered by Magotteaux Thailand when the duties were in force.
 - i. The duty should continue after 10 years to protect the domestic industry and the domestic producers who are MSME's; to counter the effect of concessions and benefits received by Magotteaux Thailand; significant dumping and injury margin determined as per price offers by Magotteaux India, freely disposable capacity and inventory available with the respondent; and the dumping in third country.
 - j. The impact of the duties on the end consumer has been re-calculated by considering the duty applicable on Magotteaux. The same is 0.009-0.014% and continue to be negligible and insignificant.
 - k. The consumers in India are getting fair prices as the domestic industry has not increased their selling price in proportion to increase in cost, have provided documents supporting the domestic industry.

L.3. Examination by the Authority

119. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry, and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined

suitably and addressed adequately in the relevant paras of the disclosure statement. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

120. As regards the contention that Welcast Steel has not given authorisation in prescribed formats, the Authority notes that Welcast Steel is a wholly owned subsidiary of AIA Engineering. As the parent company is engaged in production of the PUC and has sold the material produced by Welcast, the Authority has accepted the information. In any event, the Authority has received Format X from Welcast and have further undertaken verification of information and has satisfied itself with regard to sufficiency of information and evidence. The Authority also notes that authorisation and certificates prescribed by the Authority are for Authority's satisfaction and the same does not cause any prejudice against the interests of other interested parties.
121. As regards the name of other domestic producers who supported the application, the responding exporter did not comment on the confidentiality claimed within the prescribed time of 7 days of the receipt of non-confidential version of the document. It has been claimed by the domestic industry that disclosure of even name shall cause significant adverse effect to the party's interest. The Authority has satisfied itself with regard to the same and on being satisfied, Authority has allowed confidentiality on the name of the party. The Authority notes in this regard that it is not uncommon that even name of the parties concerned are confidential particularly when conflicting business interests of opposing parties are involved. However, the domestic industry itself fulfils the standing requirement as per rule 5(3). Therefore, the requirement of other domestic producers as supporters is not relevant for the present investigation.
122. As regards the contention that Magotteaux India need not have participated in the present investigation, the Authority notes that Magotteaux Thailand has undisputedly sold material over the injury period. There are no exports only during the POI. Further, Magotteaux Thailand itself has identified Magotteaux India as one of its sales channels. The scope of the present investigation is to ascertain likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of this duty. Such being the case, the sales channel adopted becomes very important. Also some of the price offers show country of origin of the goods as Thailand. Magotteaux India has attended the oral hearing. If Magotteaux India attended the hearing virtually, it cannot be contended that the party has no interest whatsoever in the present investigation, particularly, in a situation where the petitioners have contended significant business activities by Magotteaux India and the same has been admitted even at the time of hearing.
123. As regards apparent contradiction in performance analysis of domestic industry in respect of domestic and export market, it is clarified that the injury examination is limited only to the performance of the domestic industry in respect of sale in the domestic market. The Authority has separately examined the export performance of the domestic industry as required under causal link analysis and likelihood. The examination of export performance and the market loss or gained by the domestic industry in export markets is only in respect of the change in pattern of exports by the domestic industry found over the years.
124. As regards the statement that Magotteaux India has not imported the PUC from the exporter during the POI, the Authority has not considered that Magotteaux Thailand has sold the material to Magotteaux India during the POI. The Authority has held that there is no import of the PUC from Thailand. However, in a situation where there were no imports of the PUC during the POI, the rules require the Authority to ascertain likelihood of recurrence of dumping. Further, there were exports made by Magotteaux Thailand in the injury period. The Authority has considered all information and evidence available on record to ascertain the likelihood of recurrence of dumping in the event of cessation of duty.
125. As regards the contention that Magotteaux India response was not necessary, the authority has examined the submissions made by Magotteaux Thailand, domestic industry and other parties and considers that the response by Magotteaux India was very important and relevant to the present case as Magotteaux Thailand itself has identified Magotteaux India as a distribution channel for export to India. The Authority has not stated that all group entities of Magotteaux Thailand should have filed questionnaire response. As the investigation concerns exports by Magotteaux Thailand, the manner in which Magotteaux Thailand will export the product to India becomes relevant for likelihood determination. However, in a theoretical situation where Magotteaux Thailand would have exported the product through one or more of its other global entities, the Authority would have required response from those entities. However, Magotteaux Thailand has not identified other global entities for the purpose of present case and therefore the Authority has not demanded response from other group companies of Magotteaux Thailand.
126. It has been claimed by the applicants that Magotteaux India has given assurance to its customers to remove the impact of the duty. The exporter/producer has stated that this claim of the applicants is merely rhetoric. The Authority notes that notwithstanding the claim of the applicants regarding the assurance given by Magotteaux India to remove the impact of the duty, Magotteaux Thailand itself has stated that it would supply some material in the event of revocation of duty.

127. Magotteaux Thailand has stated in its questionnaire response in response to the question seeking response on the impact of revocation of duty on production capacity, production, home market shipments, exports to India and other markets, or inventories relating to the production of PUC in the future that “*The Company does not expect any change in the production capacity, home market shipments, and exports to other markets (other than India). However, it is expected that the Company will receive a few orders from Indian customers and to that extent production may rise.*” Magotteaux Thailand admitted that they may export the subject goods to India in the event anti-dumping duties are revoked. This is an indication of likelihood of recurrence of dumping and injury.

128. As regards increase in production capacities and impact of the same on economic performance, the Authority notes that increase in the cost of production of AIA cannot be attributed directly with the increase in capacity. It is mainly due to increase in raw material cost. In fact, the plant where production capacities have been expanded is having conversion cost lower than the plant which did not expand the capacities.

129. As regards the allegation of monopolistic behaviour by the petitioner, the Authority notes that the petitioner does not hold the majority share in the Indian market in total demand. In fact, the majority share in the Indian market is by MSME sector which comprises of 11 players. Further, the Authority has analysed the share of Indian industry in production and consumption from the original investigation i.e., since 2010. As seen below, it is evident that the domestic industry does not have any monopolistic position in the Indian market. Further, the anti-dumping duty has played a huge role in boosting the share of MSME in production and consumption in India.

| | Original Investigation | First SSR | Present SSR |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Period of Investigation | Jan-Dec 2010 | April '16- March '17 | April '21- March '22 |
| Other Indian Producers | | | |
| Share in Consumption | 21% | 47% | 58% |
| Share in Production | 10% | 12% | 21% |

130. As regards the issue raised by the interested parties that there cannot be any justifiable reason to seek further protection since the duties were already in force for 10 years, the authority notes that the rules do not prescribe any time period for which duty should be imposed. The duties are recommended considering the dumping, injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. These factors are analyzed at appropriate sections of this final findings.

M. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

131. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury.

132. The recommended anti-dumping duty would not reduce competition, either domestically or internationally, since the Indian consumers would, be free to source the material from domestic producers, China and other markets.

133. The duty imposed on the product since last 10 years has helped the domestic industry to operate in a level playing field. It has also been contended that there is no evidence of any adverse effect of anti-dumping duty in force since last 10 years on the consumers. Rather, the domestic industry has submitted and provided letters from consumers stating that the consumers have benefited and saved costs by using the products of the domestic industry.

134. Having concluded that there is likelihood of recurrence of dumping and injury, the Authority is of the opinion that the measure is required to be extended in respect of imports from Thailand. The Authority has noted the evidence placed before the Authority in the form of extracts of annual report of Magotteaux Thailand for the year 2019-2021. It is observed that the company has reported financial losses for calendar year 2019, 2020 and 2021 despite exporting approximately 95% of the production. The Authority is of the opinion that the company is not able to get good price in other global markets and is looking for a profitable market such as India.

135. The Authority notes that Magotteaux Thailand is exporting more than 80% of the total production of the subject goods to third countries at a price below the normal value. This shows the behaviour pattern of Magotteaux Thailand. It is very likely that upon withdrawal of anti-dumping duty they are likely to dump the

subject goods in the Indian market which are presently exported to third countries that would cause injury to the domestic industry.

136. The capacity of the domestic industry and other domestic producers collectively can meet the domestic demand even after accounting of exports. Hence, imports of any quantity will be additional over and above the capacity of domestic producers. If the imports are dumped at injurious price, the domestic producers are likely to lose their market share and consequently suffer loss.

137. Magotteaux Thailand has clearly stated that its entire export sales of about 95000 MT is on “ spot sale” basis; thus leaving significant production capacities freely disposable. Further, Magotteaux Thailand has stated that it would start selling in the Indian market in the event of cessation of anti-dumping duty.

138. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

- The product under consideration is the same as defined in the previous investigations and is like article to the product produced by the domestic industry.
- The applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the requirements under the Rules.
- No injury is presently suffered as there are no imports since the imposition of anti-dumping duty.
- The domestic industry’s performance over the current period and significant share of other Indian producers in consumption clearly demonstrates that the domestic industry has not monopolized the India market.
- Analysis of the questionnaire response shows that there is sufficient potential for Magotteaux Thailand to redirect exports from its other far-off market to India and the only barrier they face is the existing anti-dumping duty.
- The producers from Thailand have a history of dumping in India, holding freely disposable production capacity, have been dumping in third countries and are significantly export oriented.
- The assessment of likely and potential performance of the applicants show that the performance of the domestic industry is likely to deteriorate if the duties cease.
- Continuation of the existing duties shall not be against public interest.
- The impact of the anti-dumping duties on the eventual end consumer is insignificant.
- There are no sufficient evidence to establish likelihood of dumping and injury from China PR.

139. Having concluded that there is likelihood of recurrence of dumping and injury, the Authority is of the opinion that the measure is required to be extended in respect of imports from Thailand. The volume of dumped and injurious imports from Thailand to India based on the price offers and to the rest of the world have been considered. However, continuation of anti-dumping duty is not recommended on imports of product under consideration from China PR.

140. Having examined the likelihood of dumping and injury to be imminent in case of expiry of the current measure in place, the Authority recommends continued imposition of Antidumping Duty in place against Thailand as recommended by the Authority vide Final Findings Notification No 7/7/2017-DGAD dated 11th June 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I and notified by the Central Government vide Notification No. 36/2018-Customs (ADD), dated 13th July 2018 for a period of five years. Accordingly, definitive antidumping duty as per amount specified in Col. 7 of the table below is recommended to be extended from the date of this notification in the event of acceptance of these recommendations by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from Thailand.

DUTY TABLE

| S. No. | Heading/ Subheading | Description of goods | Country of Origin | Country of Exports | Producer | Duty Amount In US \$ per MT |
|--------|------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 7325 9100 | ‘Grinding Media Balls’ (excluding Forged Grinding Media Balls) | Thailand | Thailand | Magotteaux Co Ltd, Thailand | 158.80 |
| 2 | -do- | -do- | Thailand | Thailand | Any other except as | 187 |

| | | | | | reflected in S.No. 1 | |
|---|------|------|----------|----------|-------------------------|-----|
| 3 | -do- | -do- | Any | Thailand | Any | 187 |
| 4 | -do- | -do- | Thailand | Any | Any | 187 |

N. FURTHER PROCEDURE

141. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority